04 - 41 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है असर

05 - दिव्यांग लोगों के बारे में बढ़ानी होगी जागरूकता

06 - ज्ञान की ऊर्जा से आलोकित- प्रकाशित हुई राजा भोज की धारा...

07 - लगातार शतरंज की प्रतियोगिता से खिलाड़ियों का बढ़ा...

A Daily News Magazine

इंदौर

बुधवार, 03 दिसंबर, 2025

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 68, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

भोपाल गैस त्रासदी

डरी हुई तत्कालीन सरकार ने जांच आयोग ही भंग कर दिया

विभूति झा

(भोपाल गैस त्रासदी का मुआवजा दिलवाने वाले वकील तथा लेखक)

गैस रिसाव और उसके भयावह परिणामों के संबंध में जाँच के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 04 दिसंबर, 1984 को ही न्यायिक जाँच आयोग के गठन की घोषणा की थी। 06 दिसंबर को गज़ट नोटिफिकेशन द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायमूर्ति एन. के. सिंह की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया गया। आयोग को तीन महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश थे। उसी गजट नोटिफिकेशन में जाँच आयोग के विचार हेतु बिन्दुओं का भी निर्धारण किया गया। आयोग को 'भोपाल ज़हरीली गैस रिसाव जाँच आयोग' नामित किया गया।

गैस विभीषिका से उत्पन्न स्थिति और उसकी जाँच में लगी सरकारी इकाइयों तथा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की स्थापना में केंद्र सरकार की भूमिका को देखते हुए मोर्चे ने तय किया कि प्रारंभिक रूप से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न्यायिक जाँच आयोग के गठन को चुनौती देना तथा यह माँग करना उचित होगा कि न्यायिक जाँच आयोग का गठन केंद्र सरकार करे। इसे ध्यान में रखते हुए मोर्चे की ओर से 12/03/85 को मध्य प्रदेश शासन को मैंने एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया। इसकी प्रतिलिपि जाँच आयोग को भी दी गई। मोर्चे ने अनुरोध किया कि कार्यवाही आगे बढ़ाने के पूर्व आयोग अपने क्षेत्राधिकार पर विचार करे। प्रतिवेदन में मुख्य रूप से कहा गया कि-

बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन तथा उसकी भारतीय इकाई यूनियन कार्बाइड इंडिया ने केंद्र सरकार से अनुबंध कर भोपाल में कारखाना स्थापित किया। कारखाने की स्थापना में केंद्र सरकार विभागों की सहमति ली गई। गैस रिसाव के तुरंत पश्चात केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने जाँच-पड़ताल की, जिन्होंने अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए। इन सभी पर न्यायिक जाँच में विचार किया जाना अनिवार्य होगा।

जाँच के बिन्दुओं में से अधिकतर का संबंध भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की लिस्ट-1 अर्थात यूनियन लिस्ट से है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जाँच आयोग को इन बिन्दुओं पर विचार और निष्कर्ष लेने के लिए आवश्यक शक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं। इस दृष्टि से इन बिन्दुओं पर जाँच के लिए केंद्र सरकार ही सक्षम है न कि राज्य सरकार।

कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, 1952 की धारा 6-ए के अनुसार जब तक यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता कि जाँच आयोग को उत्पादन की प्रक्रिया के विषय में भी जाँच करने के लिए अधिकृत किया गया है, तब तक कार्बाइड को अपने उत्पादन की गोपनीय प्रक्रियाओं को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मप्र शासन के नोटिफिकेशन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं होने से जाँच पूरी नहीं हो सकेगी।

जाँच के बिन्दुओं में बिन्दु क्रमांक 7 पूरी तरह से असंबद्ध और अनावश्यक है। गैस रिसाव के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री का पलायन गैस रिसाव के कारणों से जुड़ा नहीं हो सकता। जाँच का यह बिन्दु केवल राजनीतिक तमाशा है, जो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने और मुख्यमंत्री की साख बचाने के लिए शामिल किया गया है।

इन सभी आधारों पर मप्र शासन से अनुरोध किया गया कि वर्तमान जाँच आयोग को समाप्त कर केंद्र सरकार से अविलंब एक सक्षम न्यायिक जाँच आयोग का गठन का अनुरोध किया जाए। इससे गैस रिसाव के कारणों और परिणामों की विस्तृत जाँच हो और निष्कर्ष सामने आ सकें।

26 मार्च, 1985 को जाँच आयोग की पहली बैठक की कार्यवाही का निरीक्षण करने के बाद मोर्चा सदस्यों ने फिर से इस संबंध में विचार किया। यह समझ बनाई गई कि पूर्व में प्रस्तुत आपत्ति को सुरक्षित रखते हुए आयोग की सुनवाई में गैस पीड़ितों का पक्ष रखना आवश्यक है। इसके मद्देनज़र 04/85 को मोर्चा ने जाँच आयोग को एक और प्रतिवेदन दिया। इसमें न्यायिक जाँच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लेने तथा दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई।

हालाँकि सोडियम थायोसल्फेट विवाद के चलते मैंने अपने आपको मोर्चा की अन्य गतिविधियों से अलग कर लिया था, लेकिन कानूनी मुद्दों पर प्रतिनिधित्व जारी रखना तय किया था। अतः आयोग के समक्ष मोर्चे का प्रतिनिधित्व मैं ही कर रहा था। संभवतः 26 जून को जब हमारे आवेदन पर सुनवाई होनी थी, तब मोर्चे की संचालन समिति के सदस्य अनिल सद्गोपाल ने आयोग की बैठक में आकर मुझसे कहा कि आवेदन वापस ले लूँ। आगे से मोर्चे की ओर से सुश्री इंदिरा जयसिंह उपस्थित होंगी, जो 'लॉयर्स कलेक्टिव' की ओर से पहले ही आयोग के समक्ष उपस्थित हो रही थीं। मैंने आवेदन वापस लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया और अपनी ओर से एक अन्य आवेदन प्रस्तुत किया, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 5-ए के अंतर्गत था। इसमें अनुरोध था कि यदि आयोग यह निर्धारित करे कि उसे जाँच के बिन्दुओं पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है, तो ऐसी परिस्थिति में अधिनियम की धारा 5-ए के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय जाँच एजेंसियों को आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करने तथा अपनी रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुतत करने के निर्देश दिए जाएं, जिससे वास्तरविक जांच हो सके (इस आवेदन की प्रति उपलब्धु नहीं है)। इन दोनों आवेदनों पर आयोग ने एक साथ सुनवाई की, जो निरंतर दो दिन चली।

मेरे आवेदन दि. 12/03/1985 के विरोध में एडवोकेट जनरल, मप्र शासन, लॉयर्स कलेक्टिव एवं भारतीय मजदूर संघ के अधिवक्ताओं तथा यूनियन कार्बाइड के अधिवक्ताओं ने भी उत्तर दिया। आयोग ने 23/07/85 को नौ पृष्ठ का विस्तृत आदेश पारित कर मेरे दोनों आवेदनों का निराकरण किया। आयोग ने पाया कि उसकी नियुक्ति उचित ढंग से हुई है और प्रदेश सरकार को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार पहला आवेदन अस्वीकार किया गया। दूसरे आवेदन पर विचार करते हुए आयोग ने कहा कि इसमें दिया गया सुझाव पूरी तरह से उचित और तार्किक है। आयोग ने सचिव को आदेश दिया कि वह तीन दिन के अंदर आवेदन में निर्देशित केंद्रीय जाँच एजेंसियों की सेवाएँ आयोग को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से सहमति प्राप्त करे, जिससे आयोग की जाँच सुचारु रूप से आगे बढ़ सके।

यह मात्र संयोग नहीं हो सकता कि आयोग के इस महत्वपूर्ण आदेश के बाद आयोग की जाँच और सुनवाई बाधित ही रही। आयोग के कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई जिस कारण बिना किसी जाँच और निष्कर्ष के दिनांक 15/12/85 को आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया। जब ऐसा प्रतीत होने लगा कि आयोग की कार्यशैली से गैस त्रासदी संभवतः वास्तविक कारण और जिम्मेदारियाँ जनसाधारण के समक्ष उजागर हो सकती हैं, तो सरकार ने ऐसे आयोग को भंग करना ही उचित समझा। हालाँकि कार्बाइड के खिलाफ कानूनी लड़ाई की दिशा में मेरे लिए यह पहला कदम साबित हुई।

(लेखक की पुस्तक 'कठघरे में साँसें: भोपाल गैस त्रासदी के चार दशक' के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

डाउनलोड करो या डिलीट, आपकी मर्जी, नहीं होगी जासूसी : सिंधिया

संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं, टेलीकॉम मंत्री का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। दूरसंचार विभाग ने भारत में बने नए या इंपोर्ट किए गए सभी मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। संचार साथी एक सरकारी मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे लेकर दावा है कि इसके साथ स्मार्टफोन चलाना ज्यादा अधिक सुरक्षित है। यह ऐप यूजर्स को अपने मोबाइल कनेक्शनों को ट्रैक करने, यह जांचने कि उनका फोन असली है या नहीं और फोन खो जाने या चोरी होने पर उसे ब्लॉक करने में मदद करता है। इसके अलावा, यह ऐप संदिग्ध कॉल, धोखाधड़ी के प्रयास और संदिग्ध लिंक को रिपोर्ट करने की सुविधा भी देता है। कल से संचार साथी को मोबाइल फोन में अनिवार्य किए जाने पर लगातार हंगामा मचा है। विपक्ष ने

सरकार पर इस ऐप के जरिए जासूसी करने का आरोप लगाया है। अब टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐप पर छिड़े बवाल के बाद इस पर स्पष्टता दी है। अब दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि संचार साथी ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है। टेलीकॉम मंत्री सिंधिया ने कहा कि ऐप से किसी की जासूसी नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, 'हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, संचार साथी एक ऐप-पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर सकता है। यह जनभागीदारी का एक कदम है। लोगों को इस पर आपत्ति नहीं स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो इससे यह पता कर सकते हैं कि नंबर फेक है।

पंजाब में किसानों का रेल रोकने का ऐलान

19 जिलों में 26 जगह पटरियों पर बैठेंगे किसान

- 5 को दो घंटे का प्रदर्शन, कोई हाई-वे नहीं रोकेंगे

अमृतसर (एजेंसी)। शंभू-खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसान मजदूर मोर्चा ने 5 दिसंबर को पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया है। मोर्चा के संयोजक सरवण पंधेर ने कहा कि पूरे प्रदेश में 26 जगह ट्रेनें रोकी जाएंगी। यह प्रदर्शन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए किया जाएगा। इस दौरान रोड जाम नहीं होगी। पंधेर ने कहा कि एमएसपी की गारंटी के कानून समेत किसानों की कई मांगों पर केंद्र और पंजाब सरकार की तरफ से फैसला नहीं लिया गया है। इसकी वजह से किसानों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन से अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और बठिंडा में सख्ती रहेगी।

चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा

मोदी सरकार ने फौरन बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया

- 8 दिसंबर को वंदे मातरम् पर चर्चा, पीएम मोदी देंगे संबोधन

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव सुधार यानी एसआईआर पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। संसद में दो दिन से फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान गया है। मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के. सुरेश ने बताया, 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही उन्होंने कहा- एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम् पर चर्चा होगी। इसके लिए भी 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पर चर्चा करा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा सोमवार 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से की जाएगी। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। वहीं, चुनाव सुधारों (एसआईआर) पर चर्चा मंगलवार 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी; चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

- **वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होगी चर्चा**- एक वरिष्ठ सांसद ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए बताया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विस्तृत और विशेष चर्चा होगी। यह चर्चा संसद के शीतकालीन सत्र का एक प्रमुख आकर्षण होने की उम्मीद है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका और समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम पहली बार 7 नवंबर, 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ था। बाद में, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस भजन को अपने अमर उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था।

विधानसभा भवन में हुई कैबिनेट बैठक

नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक योजना में 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। बैठक में नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए योजना को 2026-27 तक निरंतर जारी रखने और अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई।

वर्तमान में प्रदेश में इस योजना के तहत 1,062 परियोजनाएं, कुल 1,070 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के साथ चल रही हैं। 325 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 407 परियोजनाओं पर काम हो रहा हैं। बाकी 330 परियोजनाएं डीपीआर स्वीकृति/निविदा प्रक्रिया में हैं।

इस योजना के तहत नगरीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, सफाई, स्ट्रीट लाइट, मार्ग निर्माण, नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान विकास जैसे अधोसंरचनात्मक विकास कार्य किए जाते हैं।

नियुक्ति की शर्तें यह रहेगी- विभागीय भर्ती नियम के अनुसार एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस की अर्हता दस्तावेज 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा।

यदि किसी उम्मीदवार ने परिवीक्षा अवधि में आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए, तो उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी, बिना परिवीक्षा अवधि बढ़ाए।

सीएम ने टीम को दी बधाई- बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने संबोधन में रायपुर (छत्तीसगढ़) में हुई पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मल्हारगढ़ थाने को देश के श्रेष्ठतम पुलिस थानों की रैंकिंग में नवी रैंक मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपराध के ग्राफ आपराधिक प्रकरणों को सुलझाने की अवधि स्वच्छता अधिकारियों कर्मचारियों का व्यवहार जैसे 70 मापदंडों के परीक्षण के आधार पर प्राप्त यह रैंक प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना

बाकी अधूरे कामों को पूरा करने के लिए पूर्व में स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपए के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए चयनित 29 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

बरेली में मैरिज लॉन तोड़ने पर पुलिस से भिड़ीं महिलाएं

बरेली (एजेंसी)। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर ऐक्शन जारी है। मंगलवार को सपा नेता सरफराज बली खान और राशिद खान के मैरिज लॉन पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। मौके पर 2 बुलडोजर पहुंच चुके थे। 5 थानों की पुलिस फोर्स भी पहुंची। बुलडोजर और पुलिस टीम से महिलाओं की झड़प हो गई। इससे पहले सोमवार को पुलिस फोर्स की कमी के चलते बुलडोजर नहीं चल

सका था। बता दें, 23 नवंबर को मोहम्मद आरिफ की 3 मंजिला बिल्डिंग और दो मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर चला था। इस तरह अब तक तौकीर रजा के करीबियों की 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। तौकीर रजा पर बरेली में 26 सितंबर की हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं।

शरद की सुबह

उस काली रात में
हवा में उड़ता जहर
अंधाधुंध भागते पैर
कटे वृक्ष की तरह
गिरते लोग
भीषण ठंड में
सांसों में अंदर
घुलता जहर।

हर कोई नीलकंठ
तो नहीं हो सकता
जो निगल ले
उस हलाहल को
रोते-बिलखते बच्चे
श्मशान बनती
भोपाल की सड़कें
बिखरे शव।

और लहराता
एंडरसन
किसी प्रेत की तरह
अट्टहास लगाता
उड़ गया
हमारे खुद के
पिशाचों की मदद से
पीछे छोड़ गया
कई हजार लाशें।

आर्तनाद, चीखें
अंधे, बहरे
चमड़ी उधड़े चेहरे
लाखों मासूमों को
जो आज भी
भुगत रहे हैं
उन क्षणों को
जब एक जहर
उतरा था
भोपाल की सड़कों पर।

- सुशील कुमार शर्मा

भोपाल का तापमान

अधिकतम 27 °c

न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ बुधवार, 03 दिसंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी

- मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई,कोई विस्फोटक बरामद नहीं

मुंबई (एजेंसी)। कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ए-1234 को मंगलवार सुबह बम की धमकी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अधिकारियों के मुताबिक, हैदराबाद एयरपोर्ट को एक ईमेल मिला था, जिसमें विमान में बम होने की बात लिखी थी। इसके बाद तुरंत सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एयरबस विमान रात 1.56 बजे कुवैत से उड़ा था और सुबह 8.10 बजे मुंबई के

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। विमान को सुरक्षित तरीके से उतारकर एयरपोर्ट के अलग-थलग इलाके में ले जाया गया है, जहां बम स्क्वायड और सुरक्षा टीमें पूरी जांच कर रही हैं। यात्रियों और क्रू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि धमकी की जांच जारी है। अभी तक किसी विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई है। आगे की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद ही सामने आएगी। विमान में बम होने की सूचना मिलने पर फ्लाइट को अपने निर्धारित एयरपोर्ट के बजाय नजदीकी हवाई अड्डे पर उतारा जाता है। इससे ईंधन की खपत तो ज्यादा होती ही है, विमान की दोबारा जांच करने, यात्रियों को होटलों में ठहराने की व्यवस्था करनी पड़ती है।

जब हाईकमान कहेगा डीके शिवकुमार सीएम होंगे

- कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया बोले-हमारे बीच मतभेद नहीं

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि जब हाईकमान कहेगा, तब डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उन्होंने यह बात शिवकुमार को कब सीएम बनाया जाएगा से जुड़े सवाल पर कही। सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और दोनों राज्य सरकार को एकजुट होकर चला रहे हैं। इससे पहले दोनों ने मंगलवार को फिर साथ में ब्रेकफास्ट किया। ये 4 दिन में दूसरी बार है जब दोनों की साथ

में नाश्ते पर मीटिंग हुई। सिद्धारमैया मंगलवार सुबह शिवकुमार के घर पहुंचे, जहां उनका स्वागत डीके शिवकुमार और उनके भाई, पूर्व सांसद डीके सुरेश ने किया। इसके बाद तीनों ने साथ बैठकर पारंपरिक नाटी चिकन और इडली लुत्फ उठाया। दरअसल दोनों नेताओं की ये मुलाकातें हाईकमान के आदेश के बाद हो रही हैं। पिछले 22 दिनों से दोनों गुटों के कार्यकर्ता अपने-अपने नेता को सीएम पद पर देखना चाह रहे है। 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5-2.5 साल की डील हुई थी, लेकिन सिद्धारमैया समर्थक इसे नकारते आए हैं।

अब सेवातीर्थ के नाम से जाना जाएगा पीएमओ

मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सब कुछ होगा हाईटेक

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर अब सेवातीर्थ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) जल्द ही साउथ ब्लॉक के अपने पुराने दफ्तर से निकलकर नए 'सेवा तीर्थ' कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएगा।

यह बड़ा बदलाव दशकों बाद हो रहा है। नया पीएमओ सेवा तीर्थ-1 से काम करेगा, जो एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव-1 में बनी तीन नई आधुनिक इमारतों में से एक है। इसी कॉम्प्लेक्स की सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3 इमारतों में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस होगा। यह शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर को कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों के साथ सेवा तीर्थ-2 में एक अहम मीटिंग भी की थी। यह नया कॉम्प्लेक्स सरकारी कामकाज को और

तेज बनाएगा और भारत सरकार के काम करने के तरीके में एक नया अध्याय लिखेगा। यह नया सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स वायु भवन के पास एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव-1 में बनाया गया है। इसमें तीन शानदार इमारतें हैं। इनमें से पहली इमारत,सेवा तीर्थ-1, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का नया घर बनेगी। यह साउथ ब्लॉक से दशकों बाद हो रहा एक बड़ा बदलाव है। बाकी दो इमारतें, सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3, भी इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं। सेवा तीर्थ-2 में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का दफ्तर होगा। यह वो जगह है जहां सरकार के बड़े फैसले लिए जाते हैं। सेवा तीर्थ-3 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस होगा। एनएसए देश की सुरक्षा से जुड़े अहम मामलों को देखते हैं। यह शिफ्टिंग का काम अब शुरू हो गया है। हाल ही में, 14 अक्टूबर को, कैबिनेट सेक्रेटरी ने महत्वपूर्ण मीटिंग की थी।

पीएम मोदी जब बोलते हैं तो दुनिया के दिग्गज सुनते हैं

यह है भारत की बढ़ती ताकत,मोहन भागवत का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि भारत की शक्ति अब दुनिया के सामने दिखाई देने लगी है और देश अपनी उचित वैश्विक भूमिका वापस पा रहा है। भागवत ने कहा कि शताब्दियों या जयंती जैसे पड़ाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन असल ध्यान समय पर काम पूरा करने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को

जोड़ने का काम अभी अधूरा है और संघ को आत्ममंथन करना चाहिए कि इस कार्य में इतनी देर क्यों लगी। संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, जब भारत उठता है तो वैश्विक समस्याओं का समाधान मिलने लगता है, संघर्ष कम होते हैं और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया को भारत से यही उम्मीद है और संघ कार्यकर्ता इसी लक्ष्य के प्रति शुरू से समर्पित रहे हैं।

कनाडा में हरियाणा के युवाओं को रोजगार में मिलेगी प्राथमिकता

- सीएम की कनाडा राजदूत से मीटिंग, वेस्ट एनर्जी-विद्युत उत्पादन में भागीदारी पर चर्चा

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा के युवाओं को कनाडा में रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने इसको लेकर चंडीगढ़ में मीटिंग की। मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात में हरियाणा के साथ नए सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते बढ़ाना बैठक का उद्देश्य रहा। मीटिंग में तय किया गया कि हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को कनाडा में रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी, विद्युत उत्पादन और कनाडा में खनन क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई। चंडीगढ़ में मीटिंग के दौरान तय किया गया कि कनाडा में प्रदेश के कुशल उद्यमियों को व्यापार स्थापित करने में भी कनाडा मदद करेगा। कनाडा के विश्वविद्यालय को प्रदेश में स्थापित करने और निवेशकों के हरियाणा में निवेश के विस्तृत रोडमैप पर भी सीएम

सैनी और कनाडा के राजदूत की चर्चा हुई। विदेश सहयोग विभाग के सौजन्य से दोनों पक्षों के बीच ये मुलाकात कराई गई। इससे पहले 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की टोक्यो में जापानी कंपनियों के निवेशकों और उद्यमियों से मुलाकात हुई थी। इस दौरान कपड़ा समाधान और उन्नत सामग्री निर्माण में विश्व स्तर पर काम करने वाली सेइरेन कंपनी के साथ समझौता (एमओयू) किया गया।

कटनी कलेक्टर की बात सुन दुखी हुआ मजदूर

केबिन के सामने किया आत्मदाह का प्रयास, पेट्रोल लेकर पहुंचा था जन सुनवाई में

कटनी (नप्र)। कटनी कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान एक मजदूर ने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल आत्मदाह का प्रयास किया। पूरा घटनाक्रम कलेक्टर केबिन के सामने हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

आत्मदाह का प्रयास करने वाले मजदूर का नाम भारत पटेल है। वो स्लीमना बाद थाना क्षेत्र के धुरी ग्राम का रहने वाला है। भारत पटेल ने बताया कि वह एक साल से लगातार जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाने के लिए आ रहा है, लेकिन उसे अब तक इंसाफ नहीं मिल सका है। इसलिए उसने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की। परेशानी के कारण उसने आज यह आत्मघाती कदम उठाने का फैसला किया।

क्या है मामला- भारत पटेल का कहना है कि पिछले साल 23 दिसंबर 2024 को ग्राम के ही कुछ दबंगों ने थाने में पुलिसवालों से उसकी पिटाई कराई थी। पूरे शरीर पर चोटें आई थीं। उससे उठते-बैठते तक नहीं बनता है। इस वजह से उसे अभी भी इलाज कराना पड़ रहा है।

उसने शुरुआत में तो इलाज कराया, लेकिन अब आर्थिक समस्या के चलते वह आगे का इलाज कराने में असमर्थ है। उसकी हालत दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है, लेकिन उसे सरकारी अस्पताल में भी उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है।

कलेक्टर की बात सुन हुआ दुखी- पीड़ित का कहना है कि आज कलेक्टर को अपनी पूरी समस्या बताई। उन्होंने हर बार की तरह आज फिर केवल जिला अस्पताल में जाकर इलाज कराने की सलाह दी। उधर, पुलिस भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें शह दे रही है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार...- जनसुनवाई में मेरी फरियादी से मुलाकात हुई। उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बताई थी। मैंने तत्काल जिला अस्पताल की टीम को निर्देशित किया था और उनके साथ उन्हें जाने के लिए भी मनाया था। ऑर्थोपेडिक सर्जन से उनका अपॉइंटमेंट भी फिक्स कराया था। बाहर निकलने के बाद उन्होंने कुछ इस अप्रिय घटना को अंजाम दिया है। उनको जिला अस्पताल भेजा गया है जहां उनका उपचार जारी है।
आशीष तिवारी, कलेक्टर

फरियादी का जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद है। स्लीमनाबाद थाने में दोनों पक्षों की ओर से मामला भी पंजीकृत है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके, पुलिस पर एक-पक्षीय कार्रवाई करने की शिकायत फरियादी द्वारा की जा रही है। जिस पर फरियादी को समझाया गया है और उनकी शिकायत को विस्तार से समझा भी गया है। अगर फिर भी कोई शिकायत है, तो उस पर न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।
- अभिनय विश्वकर्मा,
पुलिस अधीक्षक

नौसेना ने पाकिस्तानी नेवी के खिलाफ की मजबूत तैनाती

- भारतीय नौसेना प्रमुख बोले- ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी

अरब सागर में लगातार ऑपरेशंस चल रहे, पाक को नुकसान

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। मई 2025 में शुरू हुए इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नेवी के खिलाफ मजबूत तैनाती की। इसके कारण पाकिस्तान नौसेना अपने जहाज बंदरगाहों से बाहर नहीं निकाल सकी और अरब सागर के पास मकरान तट तक ही सीमित होकर रह गई। नेवी चीफ ने कहा कि बीते 7-8 महीने से पश्चिमी अरब सागर में हमारे ऑपरेशन लगातार जारी है। इससे चलते पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यापारी जहाजों के रूट कम हुए हैं। उनकी बीमा राशि महंगी हुई है। इसके चलते पड़ोसी

देश पर वित्तीय दबाव बढ़ा है। नेवी चीफ ने मंगलवार को दिल्ली में नेवी की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के अभियान में नेवी यूनिट्स ने पिछले साल अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर 43,300 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए। हम पहले रिस्पॉन्डर के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बहुत प्रभावी तरीके से निभा रहे हैं और हमें इस पर गर्व है।

इंसानियत के नाते भारत ने पाक के लिए खोल दिया एयरस्पेस

मदद लेकर श्रीलंका जाएगा विमान, पहलगाम हमले के समय बंद किया था

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने तूफान दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लिए राहत सामग्री ले जा रही पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट को अपने एयरस्पेस से गुजरने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी सिर्फ 4 घंटों के अंदर दी गई। ओवरफ्लाइट यानी, जब कोई विदेशी विमान किसी देश की सीमा के ऊपर से गुजरता है, लेकिन वहां लैंड नहीं करता, तो उसे ओवरफ्लाइट कहते हैं। सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे भारतीय एयरस्पेस के ऊपर से उड़ान भरने की रिक्वेस्ट की थी। पाकिस्तान ने 1 दिसंबर को ही ओवरफ्लाइट इजाजत मांगी थी।

इसका मकसद श्रीलंका को मानवीय मदद देना बताया गया। इसे देखते हुए भारत ने बहुत तेजी से रिक्वेस्ट प्रोसेस की। इस दौरान सोमवार को 5.30 बजे आधिकारिक चैनलों के जरिए पाकिस्तानी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजरने की परमिशन दी गई। इसकी जानकारी पाकिस्तान सरकार को दे दी गई। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया था।

डॉ. शाहीन की कार से मिली असाल्ट राइफल-पिस्टल

- अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी ब्रेजा कार में छिपाई थी
- दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए ने 30 डॉक्टरों के लिए बयान

फरीदाबाद (एजेंसी)। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल लेडी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। ब्लास्ट के बाद शाहीन को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी उसकी ब्रेजा कार से जांच के दौरान एक 'क्रिनकोव' असाल्ट राइफल और एक विदेशी पिस्टल बरामद हुई थी। 13 नवंबर को बरामद इस कार की जानकारी अब सामने आई है। यही वह कार है, जिसे 25 सितंबर 2025 को खरीदा गया था। एजेंसी से कार की डिलीवरी के समय डॉ. शाहीन के साथ डॉ. मुजम्मिल शकील भी था। सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी तस्वीर डाली गई थी। सूत्रों के मुताबिक, डॉ. शाहीन की कारों को अक्सर डॉ. मुजम्मिल इस्तेमाल करता था। जिन गाड़ियों में विस्फोटक सामग्री की ढुलाई की गई थी, वे भी डॉ. शाहीन और

डॉ. उमर नबी के नाम ही थी। इसी बीच यूनिवर्सिटी में जब शाहीन के कमरे की तलाशी ली तो वहां बनाए गए सीक्रेट लॉकर से 18.50 लाख कैश, सोने के 2 बिस्कुट, खाड़ी देशों की करेंसी बरामद हुई थी। डॉ. शाहीन अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की गिरफ्त में है। एजेंसी अभी तक यूनिवर्सिटी के 30 डॉक्टरों के बयान भी दर्ज कर चुकी है। इन डॉक्टरों में अधिकतर जम्मू-कश्मीर से संबंध रखते हैं। जांच एजेंसी इन डॉक्टरों का बैकग्राउंड खंगाल रही है। डॉ. शाहीन ने 25 सितंबर को फरीदाबाद के नीलम चौक स्थित शोरूम से यह ब्रेजा कार खरीदी थी। इस गाड़ी को 10 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट देकर खरीदा गया था। गाड़ी की डिलवरी लेते समय डॉ. मुजम्मिल साथ में गया था। दोनों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी थी।

दिल्ली ब्लास्ट के अगले दिन हुई डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी

10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के सामने डॉ. उमर नबी ने खुद को विस्फोट से लदी आई 20 कार समेत उड़ा लिया था। अगले ही दिन यानी 11 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस के इनपुट पर फरीदाबाद पुलिस ने डॉ. शाहीन को हिरासत में लिया था। पुलिस ने जब हॉस्टल के ब्लॉक नंबर 15 में उसके फ्लैट नंबर 32 की तलाशी ली तो पुलिस को वहां पर नई ब्रेजा कार चाबी मिली। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें हथियार मिले। हालांकि तब इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। शाहीन की गाड़ी से पुलिस को जो क्रिनकोव असाल्ट राइफल बरामद हुई, वह काफी अहम है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह देखने में भले ही छोटी लगती हो, लेकिन इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कम जगह पर आसानी से रखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि कॉम्पैक्ट राइफल 1979 में सोवियत संघ में बनाई गई थी। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के पकड़े जाने के बाद की गई पूछताछ में डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आया।

चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान

इंदौर। चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद शहरभर में पुलिस ने युद्धस्तर पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में पुलिस ने प्रतिबंधित मांझे का बड़ा जखीरा जब्त कर कई विक्रेताओं पर प्रकरण दर्ज किए। पुलिस के अनुसार सबसे बड़ी कार्रवाई चंदन नगर थाना क्षेत्र में हुई, जहां सिंहासा राम मंदिर के पास चाइनीज मांजा बिकने की सूचना मिली थी। दबिश के दौरान समीर उर्फ मोनू पिता अकील मेव को पकड़ा गया। उसकी तलाशी में 12 कार्टून से 648 गट्टे मिले, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख 25 हजार रुपए बताई गई है। इस क्रम में आजाद नगर पुलिस ने नगमा खान निवासी गोप कॉलोनी से 40 गट्टे जब्त किए। वहीं राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में एक पतंग दुकान पर छापे में नाबालिग के पास से 6 घिरनियां पकड़ी गईं। परदेशीपुरा क्षेत्र की लाल गली में की गई कार्रवाई में हीरालाल पिता हरि गौड़ के पास से 84 गट्टे बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 42 हजार रुपए है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है।

अवैध लकड़ी परिवहन पर कार्रवाई, वाहन जब्त

इंदौर। अवैध लकड़ी परिवहन पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वन विभाग की टीम ने गुरु नानक टिंबर मार्केट (लकड़ी मंडी) क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक वाहन को पकड़ा, जिसमें नीम सहित अन्य प्रजातियों की गोल लकड़ी भरी हुई थी। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध वाहन को रोका। वाहन चालक और आरोपी विकास अहिरवार लकड़ी को सांवेर रोड की ओर से लकड़ी मंडी ला रहा था। प्रारंभिक जांच में परिवहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर वन विभाग ने वाहन सहित लकड़ी को जप्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएफओ प्रदीप मिश्रा के निर्देश पर विभाग की टीमें लगातार रात में गश्त कर रही हैं। बताया गया कि हाल ही में अवैध लकड़ी परिवहन की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए यह निगरानी और सख्त की गई है।

एमवाय में 15 किलो के दो ट्यूमर निकाले गए

इंदौर। एमवाय अस्पताल के सर्जरी विभाग ने एक और बड़ी चिकित्सा उपलब्धि दर्ज करते हुए खरगोन जिले के ग्राम दबिया की 50 वर्षीय महिला मसाली बाई का अत्यंत जोखिमपूर्ण ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। पेट में तेज दर्द और सूजन की शिकायत पर भर्ती की गई महिला की जांच में पाया गया कि उनके पेट में लगभग 15 किलो वजन के दो विशालकाय ट्यूमर मौजूद हैं, जो उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुके थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभागाध्यक्ष डॉ अरविंद शुक्ला के नेतृत्व में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ सोमेन भट्टाचार्जी तथा सर्जरी टीम के डॉ. अविनाश गौतम, डॉ. उपेंद्र पांडेय, डॉ. रामेंद्र गुर्जर सहित अन्य चिकित्सकों ने कई घंटों तक चले जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर्जरी के दौरान दोनों बड़े ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल लिए गए। बड़ी सर्जरी के बावजूद मसाली बाई की स्थिति पूरी तरह स्थिर रही और उपचार के बाद उन्हें सोमवार को अस्पताल से स्वस्थ अवस्था में डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने टीम के उत्कृष्ट प्रयासों और समय पर किए गए उपचार की सराहना की है, जिसके चलते मरीज की जान सुरक्षित बचाई जा सकी।

शातिर स्नेचर से 5 मोबाइल जब्त

इंदौर। पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपी और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पलासिया की टीम ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 5 मोबाइल और वारदात में उपयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसकी कुल कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ऋषि उर्फ गोल्डी कामले निवासी मानवता नगर भूरी टेकरी और उसका नाबालिग साथी नशे की लत पूरी करने के लिए राहगीरों से मोबाइल झपट कर सस्ते दामों में बेच देते थे।

पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाया

इंदौर। तलाक को लेकर पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग युवक को परेशान कर रहे थे। लगातार प्रताड़ित होने के चलते उसने जहर खाकर जान दे दी थी। जांच के बाद पुलिस ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के नया बसेरा का है। पुलिस के अनुसार, मृतक का नाम संजय (30) पिता भोलाराम अवासे है। उसने शनिवार शाम को जहर खा लिया था। तबीयत बिगड़ने पर उसे परिजन नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां रविवार दोपहर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई नीलेश ने बताया कि संजय मजदूरी का काम करता है। उसने 6 साल पहले मुस्कान खरे नाम की महिला से प्रेम विवाह किया था। मुस्कान से उसके दो बच्चे हैं। दीपावली के समय मुस्कान अपनी मां के घर चली गई। इसके बाद वह लगातार संजय पर तलाक को लेकर दबाव बना रही थी। उसने पुलिस में भी संजय को लेकर शिकायत की थी। दोनों के बीच शनिवार को मोबाइल पर काफी देर तक बात हुई। इसके बाद संजय ने यह जानलेवा कदम उठा लिया। नीलेश के मुताबिक, संजय को उसकी पत्नी के अलावा सास सपना और उसकी नानी भी परेशान कर रही थी। पुलिस ने परिवार के आरोप के बाद मामला जांच में लिया है।

युवती के विवाद में फायर, 3 घायल

तेजाजी नगर क्षेत्र में देर रात विवाद

इंदौर। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में युवती के विवाद में मारपीट के बाद कट्टे से फायर किया गया। मारपीट में तीन लोगों को चोट आई है। देर रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने फरियादी राजीव पटेल निवासी मोरोद की शिकायत पर मुख्य आरोपी श्याम मस्करा, करण मस्करा, जितेंद्र पटेल, बबलू चंदेल और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी इशबा कॉलेज विजय नगर से ग्रेजुएशन कर रहा है। उसने बताया कि उसकी लोट्स गार्डन में रहने वाली युवती से लगभग छह माह से बातचीत थी। एक सप्ताह पहले युवती के भाई करण ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह दोबारा उसकी बहन से बात करेगा तो ठीक नहीं होगा। 30 नवंबर की रात करीब 10 बजे मैं अपने दोस्त इशु सिकरवार की बारात से दोस्त अरुण पटेल के साथ उसकी मोटरसाइकिल से मोरोद आ रहा था। जैसे ही वे ग्राम मोरोद श्मशान घाट के पास पहुंचा, वहां रोड किनारे खड़ी काले रंग की स्कार्पियो और मारुति कार से कुछ लोग बाहर निकले और उनका रास्ता रोक लिया। राजीव ने खंभे की रोशनी में आरोपियों की पहचान श्याम मस्करा, करण मस्करा, जितेंद्र पटेल, बबलू चंदेल और अन्य के रूप में की। राजीव पटेल के विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें गालियां दीं और हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद करण जितेंद्र और बबलू ने अपनी गाड़ियों से डंडे निकालकर राजीव और अरुण को मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान मुख्य आरोपी श्याम मस्करा ने अपनी बंदूक से राजीव पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। राजीव तुरंत नीचे बैठ गया, जिससे गोली उसके पास से निकल गई।

शोर सुनकर लड़का आया- शोर सुनकर राजीव का उसका दोस्त लोकेश मौके पर आ गए और बीचबचाव करने लगे। मारपीट में राजीव के दाहिने पैर और दोनों हाथों पर बुआ के बेटे आशीष के सिर, बाएं पैर और दोनों कंधों पर, जबकि अरुण को पीठ में चोट आई है। पुलिस मामले की जांच रही है।

दिसंबर में सर्दी फिर कहर बरपाएगी

कई शहरों में रात का पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंचने का अंदेशा

नई दिल्ली। पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, इस कारण अभी उत्तरी हवाएं कमजोर हैं। लेकिन, 3 दिसंबर के बाद, जब यह सिस्टम आगे बढ़ेगा तो फिर बर्फीली हवाएं चलने लगेंगी। इसके प्रभाव से मध्यप्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सर्दी बढ़ेगी। इस दौरान कई शहरों में शीतलहर चलेगी। मध्य प्रदेश में अबकी बार नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी। भोपाल में पारा 5.2 डिग्री पहुंच गया, जो 84 साल में सबसे कम रहा। 16 दिन शीतलहर चली, जबकि 18 दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। वहीं इंदौर में 25 साल में सबसे ज्यादा सर्दी रही। अब दिसंबर भी ऐसा ही रह सकता है। कई शहरों में रात का पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच सकता है और कोल्ड वेव का अलर्ट है। हिमाचल का रोहतांग पास बर्फ की चादर ओढ़ चुका है, हालांकि 4-5 दिसंबर को फिर बारिश-बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं, मनाली समेत राज्य के 15 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है।

प्रदेश में टूटा 84 साल का रिकॉर्ड

मध्य प्रदेश में अबकी बार नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी। भोपाल में पारा 5.2 डिग्री पहुंच गया, जो 84 साल में सबसे कम रहा। वहीं इंदौर में 25 साल में सबसे ज्यादा सर्दी रही। अब दिसंबर भी ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग की माने तो दिसंबर में कई शहरों में रात का पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच सकता है। वहीं, कोल्ड वेव भी चलेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में सबसे ज्यादा असर रहेगा। हालांकि, अगले दो दिन तक तेज ठंड से राहत मिलेगी। सोमवार को दिन में सर्द हवाओं का असर जरूर है। प्रदेश में 20 दिसंबर से कड़ाके की ठंड का दौर आता है, जो जनवरी तक बना रहता है। पिछले 10 साल में ऐसा ही ट्रेंड रहा है। इस बार भी कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव का असर रहेगा। सबसे ज्यादा सर्दी उज्जैन, ग्वालियर-चंबल संभाग में रहेगी। वजह यहां बर्फीली हवाओं का सीधे आना है।

नवंबर में ऐसे तोड़ा रिकॉर्ड

नवंबर में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। भोपाल में लगातार 15 दिन तक शीतलहर चली। रिकॉर्ड के अनुसार, साल 1931 के बाद शीतलहर के यह सबसे ज्यादा दिन है। दूसरी ओर, 17 नवंबर की रात में पारा 5.2 डिग्री तक पहुंच गया, जो ओवरऑल रिकॉर्ड भी रहा। इससे पहले 30 नवंबर 1941 में तापमान 6.1 डिग्री रहा था। इंदौर में भी पारा 6.4 डिग्री ही रहा। यहां भी सीजन की सबसे सर्द रात रही। 25 साल में पहली बार पारा इतना लुढ़का। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ दिव्या ई. सुरेंद्रन बताती हैं, इस बार उत्तरी राज्यों में नवंबर के पहले ही सप्ताह में बर्फबारी होने लगी। इस वजह से ठंडी हवाएं प्रदेश में पहुंची। आखिरी सप्ताह में हवा की दिशा बदल गई। जिससे ठंड का असर कम रहा है।

3 दिसंबर से शीतलहर का अलर्ट

ठंड के लिए दिसंबर-जनवरी खास

मौसम विभाग के अनुसार, जिस तरह मानसून के चार महीने (जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर) में से दो महीने जुलाई-अगस्त महत्वपूर्ण रहते हैं और इन्हीं में 60 प्रतिशत या इससे अधिक बारिश हो जाती है, ठीक उसी तरह दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इन्हीं दो महीने में प्रदेश में उत्तर भारत से सर्द हवाएं ज्यादा आती हैं। इसलिए टेम्प्रेचर में अच्छी-खासी गिरावट आती है। सर्द हवाएं भी चलती हैं। पिछले 10 साल के आंकड़े यही ट्रेंड बताते हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के एक्टिव होने से दिसंबर में मावठा भी गिरता है। इससे दिन में भी सर्दी का असर बढ़ जाता है।

दिसंबर की ठंड के हाल

दिसंबर में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। वहीं, उत्तरी हवाएं आने से दिन-रात के तापमान में गिरावट होती है। इस बार भी यही अनुमान है। ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। यहां बर्फीली हवाएं सीधे आएंगी। भोपाल संभाग के सीहोर-विदिशा में ठंड का जोर रहेगा। सागर संभाग के निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़-पन्ना, रीवा संभाग के मऊगंज, सीधी-सिंगरौली में तेज ठंड पड़ेगी। जबलपुर संभाग के मंडला-डिंडौरी, इंदौर संभाग के इंदौर, धार और झाबुआ में कड़ाके की ठंड रहेगी। मौसम एक्सपर्ट की माने तो दिसंबर में प्रदेश के कई शहरों में कोल्ड वेव यानी सर्द हवाएं चलेंगी। जनवरी में यह 20 से 22 दिन तक चल सकती है।

इंदौर में अभी तक 70% से ज्यादा मतदाता सूची पुनरीक्षण, जल्द ही शत-प्रतिशत काम

भारत निर्वाचन आयोग के सचिव की बूथ लेवल अधिकारियों-सुपरवाइजर से चर्चा

इंदौर। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव विनोद कुमार ने इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कामों को सराहा। उन्होंने कहा कि इंदौर में यह अभियान पूर्ण पारदर्शिता, टीम भावना, गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रणाली और तकनीक के प्रभावी उपयोग के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस स्पीड से काम जारी रहा तो इंदौर जिला अपने निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा के अंदर ही हासिल कर लेगा।

सोमवार को कलेक्टर ऑफिस में आयोजित समीक्षा बैठक में विधानसभा वार प्रोग्रेस की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इंदौर में किए जा रहे नवाचार अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक है। बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजर से भी सीधी बातचीत की। क्षेत्रवार प्रोग्रेस, अनुभव और समस्याओं की जानकारी ली और समाधान के निर्देश दिए। वे बोले- एक विधानसभा क्षेत्र के सफल नवाचारों को अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाए, जिससे अभियान और ज्यादा प्रभावी हो सके। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में प्रोग्रेस अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रही थी, लेकिन कम समय में इंदौर ने जिस स्पीड और गुणवत्ता के साथ काम किया है वह वाकई प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि इतना बेहतर परिणाम मिलेगा, यह विश्वास नहीं था। अधिकारियों को

समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति के लिए अधिकतम प्रयास करने के निर्देश भी दिए। सचिव ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए इसे गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाना आवश्यक है।

इतना डिजिटाइजेशन पूरा

बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 28 लाख 67 हजार 294 मतदाता है, इनमें से 20 लाख 13 हजार 850 मतदाताओं की जानकारी डिजिटाइजेशन हो गई है। इस तरह जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम 70 प्रतिशत से ज्यादा पूरा हो गया है। तेज गति से काम जारी है। लक्ष्य निर्धारित समय के पहले पूरा हो जाएगा। बताया गया है कि जिले में विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में 82.35%, इंदौर-1 में 63.37%, इंदौर-2 में 60.82%, इंदौर-3 में 67.76%, इंदौर-4 में 64.34%, इंदौर-5 में 62.99%, महू में 81.64%, राऊ में 65.95% और सांवेर में लगभग शत-प्रतिशत काम पूरा हो गया है। बैठक में अपर कलेक्टर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवजीवन विजय पवार, सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी और संयुक्त कलेक्टर अजीत श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सलमान फ़ारसी इस्लामिक क्विज में अल-हिरा का कामयाबी का परचम

3000 से ज़्यादा प्रतियोगियों में अल-हिरा के 6 बच्चे अव्वल

इंदौर। शहर की सलमान फ़ारसी इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता में अल-हिरा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी उत्कृष्ट योग्यता का परिचय दिया। प्रतियोगिता में शहर के सैकड़ों स्कूलों और मदरसों के तीन हज़ार से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से अल-हिरा के छह विद्यार्थियों ने टॉप-10 में स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता तीन राउंड में आयोजित की जाती है, जिसके लिए प्रतिभागी महीनों तक एक किताब के ज़रिए क्विज की तैयारी करते हैं। इस वर्ष भी अल-हिरा के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फाइनल राउंड में कुल 54 विद्यार्थियों के साथ प्रवेश किया। फाइनल राउंड का आयोजन शगुन गार्डन, इंदौर में हुआ, जहाँ बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर परीक्षकों की जमकर सराहना बटोरी और ट्रॉफी, प्रमाणपत्र तथा हज़ारों रुपये के नगद पुरस्कार अपने नाम किए। बॉयज़ कैटेगरी में मोहम्मद फरहान-नासिर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें 18,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। गर्ल्स सीनियर कैटेगरी में हुमैरा फ़ारूक़ी ने पाँचवाँ स्थान पाकर 10,000 रुपए का पुरस्कार जीता। इसी श्रेणी में मदीहा-आरिफ मंसूरी ने छठा स्थान प्राप्त कर 8,000 रुपए, जुवेरिया-इरफ़ान ने सातवाँ स्थान प्राप्त कर 6,000 रुपये तथा नौशीन-अब्दुल फ़रीद ने नौवाँ स्थान प्राप्त कर 4,000 रुपये का नगद पुरस्कार हासिल किया। गर्ल्स जूनियर कैटेगरी में मदीहा-अब्दुल गफ़्फार खत्री ने सातवाँ स्थान प्राप्त कर 4,000 रुपये का पुरस्कार जीतते हुए अपनी मेधा का शानदार प्रदर्शन किया। अल-हिरा के इन बेमिसाल परिणामों पर स्कूल प्रिंसिपल याक़ूब मेमन सहित वसीम अहमद, अबुज़र गौरी, इक़बाल सर, ताहिर सर, उमेर सर, अमान सर, सूफ़िया अंसारी, संगीता मैडम और रुबीना मैडम ने विद्यार्थियों को उनकी सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी।

चोरी का पूरा खेल नौकरानी ने रचाया, चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों से सोने-चांदी के जेवर बरामद किए

इंदौर। भंवरकुआं थाना पुलिस ने अग्रवाल नगर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए नौकरानी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरी का मास्टर प्लान खुद घर में काम करने वाली नौकरानी लता ने ही तैयार किया था, जिसमें उसके साथी, प्रेमी और चोरी का माल बेचने वाले आरोपी की भी पूरी भूमिका रही। पुलिस के मुताबिक, अग्रवाल नगर निवासी स्वप्निल त्रिवेदी के घर में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। घर में काम करने वाली नौकरानी लता पर परिवार को शुरू से ही शक था, क्योंकि घटना वाले दिन ही उसने अलमारी से सोने-चांदी के जेवरात चोरी किए और उसी दिन काम भी छोड़कर फरार हो गई। परिजनों ने इस पर तत्काल पुलिस से शिकायत की। भंवरकुआं पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सबसे पहले नौकरानी लता और उसकी महिला साथी को पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने चोरी में शामिल लता के प्रेमी और चोरी का माल बेचने में मदद करने वाले युवक का नाम बताया। पुलिस ने दोनों को भी हिरासत में लेकर चोरी की इस पूरी चेन का पदार्फाश कर दिया।

पत्रकारों से मारपीट मामले में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया

इंदौर प्रेस क्लब पदाधिकारी पुलिस कमिश्नर से मिले

इंदौर। तीन दिन पहले इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकार हेमंत शर्मा और कैमरा मैन राजा के साथ आरटीओ परिसर में दलालों ने मारपीट की थी। मामले में तेजाजी नगर पुलिस ने सात दलालों, जिनमें कर्मचारी भी शामिल है, पर नामजद एफआईआर दर्ज की थी। मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस ने ताबड़तोड़ दो आरोपियों अरुण पिता मुकेश सिरसाट निवासी नेहरू नगर तथा नरेंद्र पिता शंकर गोस्वामी निवासी सुखलिया को गिरफ्तार कर लिया। जबकि, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अलग-अलग टीमें रवाना की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी में विलंब होने पर पत्रकार साथियों ने विरोध जताया।

इधर, अन्य आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर सोमवार को इंदौर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर संतोषसिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक कर्दम ने कहा कि घटना को 48 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन सभी आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई न की गई तो प्रेस क्लब और शहर के पत्रकार मजबूर होकर कड़ा कदम उठाने पर विवश होंगे। कर्दम ने कहा कि मीडियाकर्मियों पर हमला लोकतंत्र की आवाज दबाने जैसा है और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है। पुलिस आयुक्त ने क्लब के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय त्रिपाठी, उपाध्यक्ष प्रियंका पांडे, सचिव अभिषेक चेंडके, कोषाध्यक्ष मुकेश तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य मनीष मक्खर, अभय तिवारी, प्रमोद दीक्षित, अंशुल मुकाती, श्याम कामले,विजय प्रकाश भट्ट सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार, छायाकार और वीडियो जर्नलिस्ट मौजूद रहे। सभी ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की।

शहर में ई-रिक्शा के लिए नया प्रयोग, चार रंगों में बांटा जाएगा

इससे पहचान में आसानी, अपराध रोकने का नवाचार

इंदौर। शहर का ट्रैफिक बिगाड़ने वाले ई-रिक्शा की मनमानी पर अब यातायात पुलिस ने नकेल डालना शुरू कर दिया। 12 हजार ई-रिक्शाओं के व्यवस्थित संचालन और अपराधिक घटनाओं को रोकने पुलिस नवाचार करने जा रही है। इसके तहत, अगले साल चार जोनों में चलाने अलग-अलग रंग दिया जाएगा। ट्रेफिक पुलिस का चार झोनों में बंटवारा हुआ है। प्रत्येक झोन में अलग-अलग रंग के रिक्शा चलेंगे। लेकिन, ये रिक्शा एक झोन छोड़कर दूसरे जोन में भी आवाजाही कर सकेंगे। दूसरे जोन में यात्रियों को ड्राप कर उन्हें वापस जोन में आना होगा। नवाचार से उनकी पहचान में न सिर्फ आसानी रहेगी, बल्कि अपराध होने पर वे आसानी से पकड़े जा सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस के इस प्रयोग से पीली रिक्शा वंचित रहेगी। पीली रिक्शा की संख्या धीरे-धीरे कम होते हुए करीब 550 के आसपास पहुंच गई। कोरोना संक्रमण काल के बाद शासन ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने ई-रिक्शा संचालन पर जोर दिया था। मात्र 25 से 30 हजार रुपए के डाउनपेमेंट पर रिक्शा सड़क पर आ जाते हैं। चूंकि, आरटीओ ने इनके रुट निर्धारित नहीं किए है, जिससे वे सम्पूर्ण शहर में सवारी के लिए आवाजाही करते

हैं। संकरा होने के कारण यह बाजार के साथ तंग गलियों तक आसानी से सवारी और माल ढो रहा है।

स्टीकर में होगी कुंडली

यातायात पुलिस को ऐसी शिकायतें मिल चुकी है कि ई रिक्शा चालकों में कई अपराधिक प्रवृत्ति के युवक हैं। जो यात्रियों से मनमाना पैसा वसूलते हैं। पैसा नहीं देने पर वे मारपीट तक करने लगते हैं। ऐसे चालकों पर लगाम कसने उनकी सारी कुंडली तैयार कर स्टीकर के रुप में रिक्शा में चस्पा की जाएगी। इससे खुद यात्री को भी चालक की शिकायत करने में आसानी रहेगी।

इससे यह फायदा होगा

कौनसा रिक्शा कहां चल रहा है, यह पता चल सकेगा। रिक्शा चालक अपराध करता है तो तुंरत पकड़ने में आसानी रहेगी। अतिरिक्त रंग या पीला रिक्शा जोनों में प्रवेश करेगा तो उस पर नजर रखी जा सकेगी। एक ही जगह, जोनों पर अत्यधिक रिक्शा खड़ी नहीं होगी, जिससे यातायात में सुधार होगा।कई जगह स्टैंड नहीं होने से ई रिक्शा चाहे जहां खड़े हो जाते हैं। कई मार्गों पर इतने रिक्शा कतार में रहते हैं कि दूसरे लोगों को निकलने में दिक्कत आती है। मनमाना किराया लेने, एक्सीडेंट करने के बाद भाग जाते हैं, जिससे उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता है। रुट निर्धारित नहीं होने से कई बार शहर के बाहर भी यात्री को ले जाते हैं। नाबालिग रिक्शा चालक बाहर होंगे। ट्रैफिक उपायुक्त आनंद कलादगी ई रिक्शा चालकों की मनमानी रोकने नवाचार किया जाना है। इसकी कार्ययोजना पर अभी काम कर रहे हैं। अगले कुछ माहों में काम शुरू करेंगे। रिक्शाओं के अलग-अलग कलर होने से उनकी पहचान में आसानी रहेगी।

संपादकीय

गैस पीड़ितों के प्रति बढ़ती बेरूखी

भोपाल गैस त्रासदी के जख्म यूं तो पीढ़ियों के लिए हैं, लेकिन दुनिया की इस भीषणतम मानवीय दुर्घटना की 42वीं बरसी पर राहत की बात कुल इतनी है कि हत्यारी यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा अब ठिकाने लगा दिया गया है। भोपाल में यूका का कारखाना उस हादसे के बाद से बंद पड़ा है। पिछले दिनों तमाम विवादों के बाद करीब 40 साल बाद उस 358 टन जहरीले कचरे को पीथमपुर में सुरक्षित तरीके से जला दिया गया है। साथ ही इस कचरे के अवशेषों को भी वैज्ञानिक लैंडफिल में दफनाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा पुनर्वास के मोर्चे पर अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। क्योंकि जिन लोगों ने उस भयावह हादसे में अपनी जानें गवां दीं, वो तो चले गए, लेकिन जो जिंदा रहे, उनमें से कई की जिंदगी नरक हो गई है। भोपाल के गैस पीड़ितों पर तो यह दोहरी मार रही है। गैस पीड़ित तो पहले से थे ही, ऊपर से कोविड ने अधमरा कर दिया है। हालांकि बीते चालीस सालों में गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने काफी काम किया है। फिर भी अपेक्षाओं का अंत नहीं है। यहां तक कि जो हुआ है, उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल में भोपाल गैस पीड़ित संगठनों ने आरोप लगाया है कि गैस पीड़ितों के लिए आवंटित 139 करोड़ रू. का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। गैस पीड़ित संगठनों द्वारा जारी सामूहिक बयान के अनुसार भारत सरकार के मंत्रियों के समूह (एमओयू) ने भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सा, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए 272.75 करोड़ स्वीकृत किए थे। यह धनराशि 75:25 के अनुपात में मध्य प्रदेश सरकार को सौंपी गई। इसमें से 139 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च ही नहीं की गई है और जो राशि खर्च में दिखाई गई है, उसका भी अधिकांश हिस्सा गैस पीड़ितों को किसी वास्तविक लाभ में परिवर्तित नहीं हुआ। संगठनों का आरोप है कि गैस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास की निधि भ्रष्टाचार का शिकार हो गई। साल 2011 से 2013 के बीच 22 प्रशिक्षण एजेंसियों को 18.13 करोड़ दिए गए ताकि वे गैस पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए 133 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकें। आरटीआई दस्तावेजों और 380 कथित लाभार्थियों के साक्षात्कार से सामने आया कि लगभग 25 प्रतिशत लाभार्थी नाम फर्जी थे, आधे से अधिक नियुक्ति पत्र जाली थे, और केवल 6 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को ही उनका स्टाइपेंड मिला। यानी लगभग 94 प्रतिशत भुगतान धोखाधड़ी पूर्ण था। विभाग ने लगभग पूरे 100 करोड़ रुपये इन निरर्थक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर खर्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन भ्रष्टाचार उजागर होने के कारण योजना रोक दी गई। इसी प्रकार गैस राहत अस्पतालों में 90 प्रतिशत विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हैं। 2021 में 3 गैस राहत अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए, लेकिन सर्जन और एनेस्थेटिस्टों की कमी के कारण एक भी बड़ी सर्जरी नहीं हुई। साल 2012 में गैस प्रभावितों को योग चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 3.63 करोड़ रुपये से 7 योग केंद्र बनाए गए। लेकिन न तो एक भी योग थेरेपिस्ट नियुक्त किया गया और न ही आज तक किसी केंद्र में कोई योग कराया गया। इन केंद्रों का इस्तेमाल अब विवाह स्थलों के रूप में हो रहा है। उधर भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कृष्ण नामदेव का आरोप है कि फंड में 5 हजार गैस पीड़ित विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन देने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन बीते 4 साल से इन महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है। वहीं 500 नई विधवाओं के नाम भी नहीं जोड़े जा रहे हैं। गैस पीड़ितों के प्रति यह बढ़ती बेरूखी सचमुच चिंता का विषय है।

41 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है असर

भोपाल गैस त्रासदी पत्थर दिल इंसान को भी इस कदर विचलित कर देने वाली थी कि हादसे में मारे गए लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया था जबकि करीब दो हजार जानवरों के शवों को विसर्जित करना पड़ा था, आसपास के सभी पेड़ बंजर हो गए थे। एक शोध में यह तथ्य सामने आया है कि भोपाल गैस पीड़ितों की बस्ती में रहने वालों को दूसरे क्षेत्रों में रहने वालों की तुलना में किडनी, गले तथा फेफड़ों का कैंसर 10 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इस बस्ती में टीबी तथा पक्षाघात के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इस गैस त्रासदी में पांच लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से हजारों लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी और जो जिंदा बचे, वे विभिन्न गंभीर बीमारियों के शिकार होकर जीवित रहते हुए भी पल-पल मरने को विवश हैं।

भोपाल गैस त्रासदी

योगेश कुमार गोयल
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

1984 में 2-3 दिसम्बर की रात भोपाल में मौत ने ऐसा तांडव मचाया था, जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हैं। भयानक गैस त्रासदी की उस घटना को पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी और हृदय विदारक औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। 2-3 दिसम्बर 1984 को आधी रात के बाद यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. (यूसीआईएल) से निकली जहरीली गैस 'मिथाइल आइसोसाइनाइट' ने हजारों लोगों की जान ली थी। उस जानलेवा त्रासदी से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। दुर्घटना के चंद घंटों के भीतर ही कई हजार लोग मारे गए थे और मौतों का यह दिल दहलाने वाला सिलसिला उस रात से शुरू होकर कई वर्षों तक अनवरत चलता रहा। हालांकि इसी साल भोपाल के जहरीले कचरे का निपटान किया जा चुका है किन्तु भोपाल गैस कांड को 41 साल बीत जाने के बाद भी इसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इस त्रासदी से पीड़ित होने वालों के जख्म आज भी हरे हैं।

भोपाल गैस त्रासदी पत्थर दिल इंसान को भी इस कदर विचलित कर देने वाली थी कि हादसे में मारे गए लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया था जबकि करीब दो हजार जानवरों के शवों को विसर्जित करना पड़ा था, आसपास के सभी पेड़ बंजर हो गए थे। एक शोध में यह तथ्य सामने आया है कि भोपाल गैस पीड़ितों की बस्ती में रहने वालों को दूसरे क्षेत्रों में रहने वालों की तुलना में किडनी, गले तथा फेफड़ों का कैंसर 10 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इस बस्ती में टीबी तथा पक्षाघात के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इस गैस त्रासदी में पांच लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से हजारों लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी और जो जिंदा बचे, वे विभिन्न गंभीर बीमारियों के शिकार होकर जीवित रहते हुए भी पल-पल मरने को विवश हैं। इनमें से बहुत से लोग कैंसर सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और घटना के 40 साल बाद भी इस गैस त्रासदी के दुष्प्रभाव खत्म नहीं हुए हैं। विषैली गैस के सम्पर्क में आने वाले लोगों के परिवारों में इतने वर्षों बाद भी शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चे जन्म ले रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गैस त्रासदी से 3787 की मौत हुई और गैस से करीब 558125 लोग प्रभावित हुए थे। हालांकि कई एनजीओ का दावा रहा है कि मौत का यह आंकड़ा 10 से 15 हजार के बीच था तथा बहुत सारे लोग अनेक

तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक करीब 8 हजार लोगों की मौत तो दो सप्ताह के भीतर ही हो गई थी जबकि करीब 8 हजार अन्य लोग रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों के चलते मारे गए थे।

हजारों लोगों के लिए काल बने और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देने वाले भोपाल में यूसीआईएल के कारखाने का निर्माण वर्ष 1969 में हुआ था, जहां 'मिथाइल आइसोसाइनाइट' (मिक) नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्ष 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइट के उत्पादन के लिए एक नया कारखाना खोला गया लेकिन भोपाल गैस त्रासदी की घटना के समय तक उस कारखाने में सुरक्षा उपकरण ठीक हालात में नहीं थे और वहां सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। उस कारखाने के टैंक संख्या 610 में निर्धारित मात्रा से ज्यादा एमआईसी गैस भरी हुई थी और गैस का तापमान निर्धारित 4.5 डिग्री के स्थान पर 20 डिग्री था। पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने काम करना बंद कर दिया था। इसके अलावा बिजली का बिल बचाने के लिए मिक को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी बंद कर दिया गया था। 3 दिसम्बर 1984 को इस कार्बाइड फैक्टरी से करीब 40 टन गैस का जो रिसाव हुआ, उसका एक बड़ा कारण माना गया कि टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के साथ पानी मिल जाने से रासायनिक प्रक्रिया होने के परिणामस्वरूप टैंक में दबाव बना और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे धमाके के साथ टैंक का सेफ्टी वाल्व उड़ गया था और यह जहरीली गैस देखते ही देखते पूरे वायुमंडल में फैल गई। अचानक हुए जहरीली गैस के इस रिसाव से बने गैस के बादल हवा के झोंके के साथ वातावरण में फैल गए और इसकी चपेट में आने वाले लोग मौत की नींद सोते गए।

जिन लोगों के फेफड़ों में सांस के जरिये गैस की ज्यादा मात्रा पहुंच गई, वे सुबह देखने के लिए जीवित ही नहीं बचे। बहुत सारे लोग ऐसे थे, जिन्होंने नींद में ही अपनी आखिरी सांस ली। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है? दुर्घटना के चार दिनों बाद 7 दिसम्बर 1984 को यूसीआईएल अध्यक्ष एवं सीईओ वारेन एंडर्सन की गिरफ्तारी हुई थी किन्तु विड़म्बना देखिये कि इतने भयानक हादसे के मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी के महज छह घंटे बाद मात्र 2100 डॉलर के मामूली जुर्माने पर रिहा कर दिया गया था। उसके बाद वह अवसर का लाभ उठाते हुए भारत छोड़कर अपने देश अमेरिका भाग गया, जिसे भारत लाकर सजा देने की मांग निरन्तर उठती रही लेकिन भारत सरकार अमेरिका से उसका प्रत्यर्पण कराने में विफल रही। 29 सितम्बर 2014 को वारेन एंडर्सन की मौत हो गई। इस हादसे से पर्यावरण को ऐसी क्षति पहुंची, जिसकी भरपाई सरकारें आज तक नहीं कर पाई हैं। सरकारों का रूख इस पूरे मामले में संवेदनहीन ही रहा। कई रिपोर्टों में इस क्षेत्र में भूजल प्रदूषण की पुष्टि होने के बाद भी सरकार द्वारा जमीन में दफन जहरीले कचरे के निष्पादन की कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। दरअसल इस भयावह गैस त्रासदी के बाद हजारों टन खतरनाक अपशिष्ट भूमिगत दफनाया गया था और सरकारों ने भी स्वीकार किया है कि यह क्षेत्र दूषित है। गैस रिसाव के करीब आठ घंटे बाद भोपाल को भले ही जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया था किन्तु हकीकत यही है कि इस गैस त्रासदी के 41 वर्षों बाद भी भोपाल उस हादसे से उबर नहीं पाया है।

वह मंजर याद करके सिहर जाते हैं लोग

भोपाल गैस त्रासदी के 41 साल
श्याम कुमार कोलारे
सामाजिक कार्यकर्ता

दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी 'भोपाल गैस त्रासदी' के हुए 41 साल, आज भी उस जहरीली भयंकर रात और डरावने दिन को याद करके लोग सिहर जाते हैं! दुनिया की सबसे बड़ी और भयानक औद्योगिक त्रासदी, जिसने चंद घंटों में ही हजारों लोगों की जान ले ली थी। कहने को तो आज इस घटना के 41 वर्ष हो चुके हैं, परन्तु इस भयानक मंजर को याद करें तो आज भी सभी का दिल दहल जाता है। 2-3 दिसंबर 1984 की रात लोगों के लिए मौत का मंजर लेकर आई थी। उस रात हवा में मौत बह रही थी, जो भी उस हवा के संपर्क में आया, मौत उसे पल में अपने आगोश में लेने को आतुर थी। आज भी उस खौफनाक रात को याद कर लोग सिहर जाते हैं! जी हाँ, मैं उसी त्रासदी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो दुनियाँ की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में इतिहास के पन्नों में दफन है। इस मंजर को याद करने से लगता है जैसे उस रात मौत का कहर लोगों को ग्रास बनाने के लिए उनके पीछे दौड़ रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएँ, किससे सहायता मांगें। बस लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़े जा रहे थे और जहरीली गैस की चपेट में आकर अपना दम तोड़ते जा रहे थे। उस काली रात ने लोगों की जीवन-साँसें छीन ली थीं। जिधर देखो उधर लाशों का ढेर नजर आ रहा था। पशु-पक्षी, मनुष्य- सब के सब लाशों के ढेर के रूप में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ मौत का तांडव चल रहा हो। उस रात जहरीली हवा के संपर्क में आने वाला कोई भी इस कहर से अछूता न रह पाया। सब किसी न किसी प्रकार से उसके प्रभाव में आए हुए थे।

मौत की इस हवा ने यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री के पास की झुग्गी-बस्ती को सबसे पहले अपना शिकार बनाया। यहाँ काम की तलाश में दूर-दराज़ गाँवों से आकर लोग रह रहे थे। इन झुग्गी-बस्तियों में रह रहे कुछ लोग तो नींद में ही मौत का ग्रास बन गए। जब गैस धीरे-धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी, तो लोग घबराकर बाहर आए, लेकिन यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। किसी ने

रास्ते में ही दम तोड़ दिया, तो कोई हाँफते-हाँफते मर गया। कोई इस तरह के मंजर से डरकर अपनी जगह से उठ भी नहीं पाया। कोई भी इस तरह के हादसे के लिए तैयार नहीं था। जैसे-जैसे रात बीत रही थी, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को यह मालूम नहीं था कि हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। उस समय किसी की आँखों के सामने अंधेरा छा रहा था, किसी का सिर चकरा रहा था और सांस की तकलीफ तो सभी को थी। कई लोगों की लाशें तो सड़कों पर ही पड़ी थीं। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड में लोगों का ढेर लगा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।

इस गैस त्रासदी को 41 साल हो चुके हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ था उस भयंकर काली रात को, जिसने हजारों लोगों को पल में मौत का ग्रास बना डाला। भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 यानी आज से 41 साल पहले दर्दनाक हादसा हुआ था। इतिहास में यह 'भोपाल गैस कांड' या 'भोपाल गैस त्रासदी' के नाम से दर्ज है। भोपाल गैस त्रासदी दुनियाँ की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना मानी जाती है। 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल स्थित कीटनाशक बनाने वाली 'यूनियन कार्बाइड' कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस 'मिथाइल आइसोसाइनाइड' का रिसाव हुआ। दरअसल, यहाँ प्लांट को ठंडा रखने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस को पानी के साथ मिलाया जाता था, लेकिन उस रात इसके संयोजन में गड़बड़ी हो गई और पानी लीक होकर टैंक में पहुँच गया। इसके बाद प्लांट के 610 नंबर टैंक में तापमान और प्रेशर बढ़ गया। इसके बाद गैस का रिसाव तेजी से होने लगा। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और जहरीली गैस पूरे भोपाल शहर में फैल गई। यह गैस हवा के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में फैल रही थी।

इसके बाद भोपाल में लाशों के ढेर लग गए। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लग गई। बताते हैं कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा था, जबकि उसे तुरंत बजना चाहिए था। जैसे-जैसे रात बीत रही थी, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को यह मालूम नहीं था कि हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ दो दिनों में ही 50 हजार से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुँचे थे, जिससे लगभग 15,000 लोगों की जान गई और कई लोग अनेक प्रकार की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के शिकार हुए, जो आज भी त्रासदी की मार झेल रहे हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार भोपाल गैस त्रासदी में कुल 3,787 मौतें हुई थीं, लेकिन गैस कांड के अगले तीन-चार दिनों में हुए अंतिम संस्कारों के आँकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। गैस कांड के बाद वन विभाग के डिपो से दाह-संस्कारों के लिए इतनी लकड़ियाँ गईं कि पाँच हजार से अधिक अंतिम संस्कार किए जा सकते थे। यह संख्या तो केवल दाह-संस्कारों की है, इसके अतिरिक्त अन्य तरीकों से हुए अंतिम संस्कार जोड़ दें तो यह आँकड़ा सरकारी आँकड़ों से कहीं अधिक प्रतीत होता है।

इस हादसे का मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन, जो इस कंपनी का सीईओ था। 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर को उसे सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहाँ से वह अमेरिका चला गया। इसके बाद एंडरसन कभी भारत नहीं लौटा। कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया था। गैस लीक होने के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया, लेकिन 1984 में हुई इस दुर्घटना से मिले जख्म 41 साल बाद भी नहीं भरे हैं। इस फाइल को भी संभवतः किसी रद्दी कागजों की फाइल में किसी कोने में दफना दिया गया होगा। किंतु आज भी उस हादसे के प्रभाव में आए लोग, जो किसी तरह बच गए थे, पथराई आँखों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार का हादसा भविष्य में कभी न हो, इसका उचित प्रबंध किया जाए और गैर-जिम्मेदारों पर कड़ा शिकंजा कसा जाए।

बेशक यह एक बहुत बड़ा औद्योगिक हादसा था, लेकिन जिस तरह का वायु प्रदूषण और उसके भीषण प्रभाव उसने भोपाल के पर्यावरण पर छोड़ा, वह आज भी दिखाई देता है। यह गैस भोपाल के तालाबों के पानी और वहाँ की हवा में लंबे समय तक घुली रही और आज 41 साल बाद भी इसका असर दिखाई देता है। उस हादसे में बचे लोगों की सेहत पर ऐसे असर हुए कि उन्हें कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियाँ हुईं, जिनका इलाज मरते दम तक चलता रहा और आज भी बचे लोगों का इलाज जारी है।

बीएलओ का कार्य दबाव नहीं, देशसेवा का विषय

मुद्दा
सपना सी.पी. साहू 'स्वप्निल'
लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

इन दिनों कुछ राज्यों से अत्यंत दुखद समाचार आए हैं कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अत्यधिक कार्य-दबाव के कारण आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा रहे हैं। यह आत्महंता बनने का समाचार बहुत हृदय विदारक है। किंतु इसी संवेदनशील मुद्दे को हमारे देश के विपक्षी दल और उनके समर्थित संगठन जिस तरह राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, वह न केवल निंदनीय है अपितु राष्ट्र-विरोधी भी है। वे सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएलओ पर अत्याचार... और सरकार उन्हें मार रही है... जैसे अतिश्योक्तिपूर्ण नारे चला रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि यही एसआईआर प्रक्रिया 2014 के बाद से हर वर्ष हो रही है और इसके कारण सिर्फ मृत व्यक्ति ही नहीं काटे जा रहे बल्कि उससे बढ़कर लाखों संदिग्ध, घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मतदाता सूची से बाहर हो चुके हैं। एसआईआर एक आवश्यक प्रक्रिया है। कुछ कड़े तथ्य असम में 2015-2024 के बीच एसआईआर और एनआरसी से संयुक्त रूप से 19 लाख से अधिक संदिग्ध विदेशी मतदाता सूची से हटाए गए (चुनाव आयोग की रिपोर्ट)।

पश्चिम बंगाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, 2024 के आंकड़ो के अनुसार यहां 2021-2024 के एसआईआर अभियानों में 22 लाख से अधिक प्रतिलिपि (डुप्लीकेट), मृत, स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए है। साथ ही 9 लाख से अधिक नए नामों को दस्तावेजों के अभाव में अस्वीकार किया गया है। त्रिपुरा, मेघालय, झारखंड के सीमावर्ती जिलों में भी एसआईआर के कारण लाखों अवैध घुसपैठिए मतदाता बनने से रोके गए। सर्वोच्च न्यायलय ने 2023 में असम मामले में स्पष्ट कहा था कि- मतदाता सूची से विदेशियों को हटाना राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है।

(अवमानना याचिका (सी) संख्या 454/2020)। पूरा देश का विपक्ष इन तथ्यों को छिपाकर केवल बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं... का एकतरफा रोना रोए जा रहा है। सब आवेदन भर सके, इसके चलते 7 दिन की अवधि बढ़ाई गई है। चुनाव आयोग ने 2024-25 के एसआईआर के लिए पहले 30 दिन का समय दिया था। कई राज्यों के बीएलओ संघों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने प्रतिवेदन दिया कि इतने बड़े पैमाने पर घर-घर सत्यापन, दस्तावेज जांच और ऑनलाइन फीडिंग में 30 दिन अपर्याप्त हैं। इसके बाद आयोग ने 2 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा अवधि 37 दिन (7 दिन अतिरिक्त) कर दी। यह बीएलओ के हित में लिया गया निर्णय है, न कि उन पर बोझ बढ़ाने का। विपक्ष का दोहरा चरित्र जिन दलों के शासनकाल में बीएलओ को बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के 60-60 दिन तक फील्ड में रखा जाता था, आज वही दल 37 दिन को भी अत्याचार बता रहे हैं। 2006-2014 के बीच पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर के नाम पर सैकड़ों भाजपा-समर्थित मतदाताओं के नाम कटवाए थे, तब बीएलओ पर कितना दबाव था, इस पर कोई बयान नहीं आया था। आज जब घुसपैठिए और डुप्लीकेट वोटरों के नाम कट रहे हैं तो अचानक बीएलओ की चिंता सताने लगी है। यह दोहरा मापदंड लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बीएलओ का कार्य साधारण ड्यूटी नहीं, राष्ट्र की रक्षा का कार्य है आप जब किसी संदिग्ध बांग्लादेशी, रोहिंग्या को मतदाता बनने से रोकते हैं, तो आप सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल देश के महान सैनिक और सुरक्षा में लगी पुलिस की तरह ही। जब आप जब किसी मृत व्यक्ति का नाम हटाते हैं, तो आप वोट की पवित्रता बचाते हैं। आप जब किसी गरीब आदिवासी महिला, जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं हैं, को फार्म-6 भरवाकर मतदाता बनाते हैं, तो आप संविधान के अनुच्छेद 326 की रक्षा कर रहे हैं।

यह कोई साधारण सरकारी काम नहीं, यह 10 लाख बीएलओ की देशसेवा है। सैनिक सीमा पर गोली खाकर देश की रक्षा करता है, आप कलम और फॉर्म से देश की आंतरिक सुरक्षा कर रहे हैं। सरकार और आयोग बीएलओ के साथ हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) पर राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सम्मानित करते हैं।

अधिकांश राज्यों में चुनाव ड्यूटी को अपार (एपीएआर) में उत्कृष्ट दर्ज किया जाता है, जिससे पदोन्नति में सीधी मदद मिलती है। इस वर्ष तो कई राज्यों ने एसआईआर के लिए अतिरिक्त मानदेय की घोषणा की है। इस लेख के माध्यम से लाखों देश हितेषी बीएलओ भाई बहनों को इतना ही समझाना है कि- प्रिय बीएलओ भाइयों-बहनों, यदि आपको वास्तव में कोई समस्या है, चाहे वह तकनीकी हो, कार्यभार की हो या स्थानीय प्रशासन के असहयोग की है तो उसे अपने ईआरओ/ एईआरओ/ डीईओ तक लिखित में ले जाइए। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आपका जीवन अनमोल है और राष्ट्र को आप जैसे देश हितैषियों की आवश्यकता है। विडंबना है कि हमारे देश का विपक्ष का काम जब मनोबल बढ़ाना है, तब वह आपके मनोबल को तोड़ रहा है, और आपको देश के लिए अमूल्य योगदान देने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। आपके साथ हम सब सच्चे भारतवासियों का काम एक सशक्त घुसपैठियों से मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना है। आप उस महान परंपरा के हिस्से हैं। जिसने 1952 से लेकर आज तक भारत के लोकतंत्र को जीवित रखा है। गर्व से अपना कर्तव्य निभाइए। देश आपकी प्रशंसा और सम्मान के साथ देख रहा है। पूरे राष्ट्रवादी जन देश सेवा में आपके सहयोगी है और आपके कार्यो पर गर्व है, चरैवेति चरैवेति... जय हिंद!

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

जब एक मंत्री का बेटा अचानक मंत्री बना

व्यंग्य
मुकेश नेमा
लेखक मप्र के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं।

एक मंत्री का बेटा अचानक मंत्री बना। अचानक इस मायने में क्योंकि बनने के कुछ देर पहले तक वो खुद इस खुश खबरी से बेखबर था।खैर बनना तो उसे ही था ,आज नही तो कल बनता,पर अचानक बना और केवल इसलिए बना क्योंकि वो उसके पापा भी मंत्री थे।

इस साधारण घटना को लेकर एक असाधारण सवाल पूछा गया नवोदित मंत्री से। आप मंत्री कैसे बने? यह सवाल पूछे जाने जैसा नही था। ऐसा सवाल था जिसका जवाब दुनिया को पहले से मालूम था, पत्रकार वैसे भी सवाल नही पूछते आजकल। ये प्रसंग इस मामले में अभूतपूर्व माना जाना चाहिए कि पत्रकार ने सवाल पूछा और मंत्री ने जवाब दिया। ये अनहोनी है और शायद इसलिए घटी है क्योंकि दोनों ही नए थे। अब पत्रकार भी कच्चा और मंत्री भी कच्चा। मंत्री कच्चा होने के बावजूद सच्चा था। सो सच बोला वो। उसने कहा,पापा से पूछिए। इस जबाब पर तालियाँ बजी। पत्रकार का मुँह उतरा और बात आई गई हो गई।

पर मुझे नहीं लगता कि इस गैर वाजिब सवाल के लिए उस पत्रकार को सस्ते में छोड़ दिया जाना चाहिए। यह सवाल बेहद बचकाना था। इस सवाल से और भी कई सवाल पैदा होते है। मंत्री का बेटा मंत्री क्यों नही बनेगा? क्या वो इसलिए मंत्री नही बन सकता कि वो मंत्री का बेटा है ? और वो मंत्री नही बनेगा तो कौन बनेगा? मंत्री का बेटा मंत्री नही बनेगा तो करेगा क्या? मंत्री का बेटा मंत्री और संत्री का बेटा संत्री। चोर का बेटा चोर और साहूकार का बेटा साहूकार। यही लोकाचार है और यही लोकतंत्र है। मंत्री के बेटे का मंत्री हो जाना उतना ही सहज है जैसे सरकारी आदमी के बीच नौकरी मे मर जाने पर उसका लड़का बाबू हो जाता है। और फिर मंत्री के बेटे का मंत्री बनने वाली ये घटना पहली हो ऐसा भी नही। मंत्री के यहाँ पैदा होने वाले लड़के की जन्मकुंडली नहीं देखी जाती। बच्चे बच्चे को पता होता है कि ये लड़का बड़ा होकर मंत्री बनेगा। पापा भी कहते है बेटा नाम करेगा। बड़ा होकर मंत्री वाले काम करेगा। ऐसे में सवाल पूछने वाले पत्रकार को यदि ये मामूली बात पता नहीं थी तो उसका पत्रकार होना ही संदिग्ध है।

मुमकिन है निहायत ग़लत वक्त पर सवाल पूछने वाला वो पत्रकार इस बात पर चकित हो कि मंत्री पुत्र आकस्मिक रूप से मंत्री बना। बिना चुनाव लड़े, बिना विधायक हुए मंत्री बना। थोड़ा जल्दी बन गया। इतने जल्दी बना कि नया कुरता भी नही सिलवा पाया। पर ये घटना भी पहली बार नही घटी। ये तो होनी थी। मंत्री के लड़के को मंत्री बनना ही था। उसकी मंजिल हमेशा से निश्चित थी। ऐसे मे वो कैसे पहुँचा, किस रास्ते से पहुँचा, उड़ कर पहुँचा या पैदल,ये बात पूछने जैसी थी नहीं।

और फिर इस बालक का सधा हुआ जवाब कमाल था। पापा से पूछिए। पापा के कारण पैदा हुआ है वो। आगे भी उसके सारे किए धरे के जिम्मेवार उसके पापा होंगे। पापा न होते तो वो भी न होता। उससे सवाल जवाब भी न होते। वो जो कुछ भी है पापा की वजह से है। आगे जो भी करेगा पापा की वजह से करेगा। ऐसे मे पापा से पूछिए ये इतना सुंदर जवाब है जिसे किसी भी सवाल के जवाब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम सभी को भी इसे गांठ में बांध लेना चाहिए।

और फिर इस ताजे ताजे बने मंत्री ने जो जवाब दिया। पापा से पूछिए। उससे अभिभूत हूँ मैं। ये भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत एक शालीन उत्तर है। ऐसे संस्कारी आज्ञाकारी बालक मिलते कहाँ है आजकल? पापा से पूछकर काम करने वाला यह नेक लड़का सवाल पूछे जाने के बजाय अभिनंदन करने योग्य है। मैं आशा करता हूँ भविष्य मे इस सच्चे मंत्री का भी बेटा होगा। बड़ा होगा। मंत्री बनेगा और उससे ऐसा बेहूदा सवाल नहीं पूछा जाएगा।

विश्व विकलांग दिवस पर विशेष

रमेश सर्राफ धमोरा
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

दिव्यांग लोगों के बारे में बढ़ानी होगी जागरूकता

सरकार द्वारा देश में दिव्यांगों के लिए कई नीतियां बनायी गयी हैं। उन्हें सरकारी नौकरियों, अस्पताल, रेल, बस सभी जगह आरक्षण प्राप्त है। दिव्यांगों के लिए सरकार ने पेशन की योजना भी चला रखी है। लेकिन ये सभी सरकारी योजनाएं उन दिव्यांगों के लिए महज एक मजाक बनकर रह गयी हैं। जब इनके पास इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए दिव्यांगता का प्रमाणपत्र ही नहीं है। इसको मानाने का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। मगर आज भी लोगों को तो इस बात का भी पता ही नहीं होता है कि हमारे आस–पास कितने दिव्यांग रहते हैं। उन्हे समाज में बराबरी का अधिकार मिल रहा है कि नहीं। किसी को इस बात की कोई फिकर नहीं हैं।

समाज में दिव्यांगता को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। जिसे सुधारने की आवश्यकता है। विश्व विकलांग दिवस पर इस वर्ष का विषय है सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए विकलांगता समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। विकलांग व्यक्तियों को अपने भाग्य को आकार देने और समाज में योगदान देने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने के महत्व को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में हर वर्ष 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाने घोषणा की गयी।

सरकार द्वारा देश में दिव्यांगों के लिए कई नीतियां बनायी गयी है। उन्हें सरकारी नौकरियों, अस्पताल, रेल, बस सभी जगह आरक्षण प्राप्त है। दिव्यांगों के लिए सरकार ने पेशन की योजना भी चला रखी है। लेकिन ये सभी सरकारी योजनाएं उन दिव्यांगों के लिए महज एक मजाक बनकर रह गयी हैं। जब इनके पास इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए दिव्यांगता का प्रमाणपत्र ही नहीं है। इसको मानाने का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। मगर आज भी लोगों को तो इस बात का भी पता ही नहीं होता है कि हमारे आस-पास कितने दिव्यांग रहते हैं। उन्हे समाज में बराबरी का अधिकार मिल रहा है कि नहीं। किसी को इस बात की कोई फिकर नहीं हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के पास एक 'दिव्य क्षमता' है और उनके लिए 'विकलांग' शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विकलांगों को दिव्यांग कहने की अपील की थी। जिसके पीछे उनका तर्क था कि शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्तियों में ईश्वर प्रदत्त कुछ खास विशेषताएं होती हैं। विकलांग शब्द उन्हे हतोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के लोगों ने विकलांगो को दिव्यांग तो कहना शुरू कर दिया लेकिन लोगों का उनके प्रति नजरिया आज भी नहीं बदल पाया है। आज भी समाज के लोगों द्वारा दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से ही देखा जाता है। भले ही देश में अनेको दिव्यांगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया हो मगर लोगों का उनके प्रति वहीं पुराना नजरिया बरकरार है।

दुनिया में अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो बताते है कि सही राह मिल जाये तो अभाव एक विशेषता बनकर सबको चमत्कृत कर देती है। भारत में दिव्यांगो की मदद के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन इतने वर्षो बाद भी देश में आज तक आधे दिव्यांगो को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुहैया कराया जा सका है। ऐसे में दिव्यांगो के लिए सरकारी सुविधाएं हासिल करना महज मजाक बनकर रह गया हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे दिव्यांग हुए हैं जिन्होंने अपने साहस संकल्प और उत्साह से विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवाया है। शक्तिशाली शासक तैमूर लंग हाथ और पैर से शक्तिहीन था। मेवाड़ के राणा सांगा तो बचपन में ही एक आंख गवाने तथा युद्ध में एक हाथ एक पैर तथा 80 घावों के बावजूद कई युद्धों में विजेता रहे थे। सिख राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख बचपन से ही खराब थी। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुधा चंद्रन के दाई टांग नहीं थी। फिल्मी गीतकार कृष्ण चंद्र डे तथा संगीतकार रविंद्र जैन देख नहीं सकते थे। पूर्व क्रिकेटर अंजन भट्टाचार्य मूकबधिर थे। वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप खेलों में झुंझुनू जिले के दिव्यांग खिलाड़ी संदीप कुमार व जयपुर के सुन्दर गुर्जर ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर भारत का मान बढ़ाया है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के पांचवें दौर का पहला चरण 2019-20 में आयोजित किया गया था। एनएफएचएस जनसंख्या, परिवार नियोजन, बाल और मातृ स्वास्थ्य, पोषण, वयस्क स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा से संबंधित प्रमुख संकेतकों पर अनुमान प्रदान करता है। एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण से एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद प्रकाशन के विश्लेषण के अनुसार भारत में विकलांग लोगों की कुल व्यापकता जनसंख्या

का 4.52 प्रतिशत है। भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक पक्ष है। यह डेटा दर्शाता है कि भारत में लगभग 6 करोड़ 32 लाख 80 हजार लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ जीवन यापन करते हैं। लोकोमोटर (गतिशील) विकलांगता सभी विकलांगताओं में सबसे आम है, इसके बाद मानसिक और वाक् (बोलने से संबंधित) विकलांगताएँ हैं।

यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में दिव्यांग आज भी अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार विश्व स्तर पर 15 प्रतिशत आबादी किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ रहती है। जबकि उसमें से 80 प्रतिशत से अधिक लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। जबकि भारत में 140 करोड़ से अधिक लोग है। इस आबादी का 2.2 प्रतिशत से अधिक लोग किसी न किसी रूप में गंभीर मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हैं। आज के प्रगतिशील युग में जहाँ सभी लोगों के एकीकरण और समावेशन पर सतत विकास के प्रवेश द्वार के रूप में जोर दिया जाता है। भारत में विकलांग लोगों को वर्गीकृत करने वाले मानदंडों की सूची को 2016 में नया रूप दिया गया था। 2016 के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम पर आधारित संशोधित परिभाषा में एसिड हमलों से संबंधित शारीरिक विकृति और चोटों को विकलांगता के रूप में मान्यता देना भी शामिल है। जो इन पीड़ितों को विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायता और समर्थन का हकदार बनाता है ।

भारत में आज भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी लोगों को मायूस होना पड़ता है। हालांकि सरकारी दावे कहते हैं कि इस प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर नजर आती है। दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जारी करने के सरकार ने जो मापदण्ड बनाये हैं। अधिकांश सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक उनके अनुसार दिव्यांगो को दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र जारी ही नहीं करते है। जिसके चलते दिव्यांग व्यक्ति सरकारी सुविधायें पाने से वचिंत रह जाते हैं।

देश में दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाएं कागजों तक सिमटी हुई हैं। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां दिव्यांगो को एक चौथाई सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। केन्द्र सरकार ने देशभर के दिव्यांग युवाओं को केन्द्र सरकार में सीधी भर्ती वाली सेवाओं के मामले में दृष्टि बाधित, बधिर और चलने-फिरने में दिव्यांगता या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में 10 साल की छूट देकर एक सकारात्मक कदम उठाया है। दिव्यांगता शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है किन्तु सबसे बड़ी दिव्यांगता हमारे समाज की उस सोच में है जो दिव्यांग जनों से हीन भाव रखती है। जिसके कारण एक असक्षम व्यक्ति असहज महसूस करता है।

अब दिव्यांग लोगों के प्रति अपनी सोच को बदलने का समय आ गया है। दिव्यांगो को समाज की मुख्यधारा में तभी शामिल किया जा सकता है जब समाज इन्हें अपना हिस्सा समझे। इसके लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है। हाल के वर्षो में दिव्यांगो के प्रति सरकार की कोशिशों में तेजी आयी है। दिव्यांगो को कुछ न्यूनतम सुविधाएं देने के लिए प्रयास हो रहे हैं। हालांकि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। पिछले दिनों क्रियान्वयन की सुस्त चाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगायी थी। दिव्यांगो को शिक्षा से जोडना बहुत जरूरी है। मूक-बधिरों के लिए विशेष स्कूलों का अभाव है। जिसकी वजह से अधिकांश विकलांग ठीक से पढ़-लिखकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं।

प्रदूषण नियंत्रण

सत्यप्रकाश नायक
लेखक जेंडर मुद्दों पर कार्यरत हैं।

भोपाल गैस त्रासदी से जलवायु संकट तक : हाशिये पर खड़ी महिलाएं

2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस सिर्फ एक तिथि नहीं–यह उस रात की कड़वी याद है जिसने देश को भीतर तक हिला दिया था। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी भारत की सबसे भयावह औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी। उस रात का असर हर परिवार ने झेला, लेकिन उसके बाद के वर्षों में महिलाओं पर पड़े स्वास्थ्य और सामाजिक बोझ गहराई से सामने आए–चाहे श्वसन समस्याएँ हों, प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम हों या लंबे समय तक बना रहने वाला मानसिक तनाव। चार दशक बाद भी एक सच्चाई नहीं बदली: पर्यावरणीय संकटों का सबसे ज्यादा असर अक्सर उन्हीं महिलाओं पर पड़ता है, जिनकी आवाज़ नीतियों में सबसे कम सुनी जाती है।

वायु-प्रदूषण की बढ़ती तीव्रता, गर्मी की लंबी लहरें, पानी की कमी और ठोस ईंधन वाले रसोईघरों का धुआँ–इन सभी जोखिमों का बोझ आज भी सबसे अधिक उन महिलाओं पर दिखता है, जो घर, खेत, ईंट-भट्टों, निर्माण स्थलों और छोटे कामधंधों की जिम्मेदारियाँ उठाती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएँ वर्षों से यह चेतावनी देती रही हैं कि ठोस ईंधन वाले रसोईघर महिलाओं के लिए 'अदृश्य जोखिम' बनते हैं। मातृ स्वास्थ्य, गर्भावस्था और नवजात बच्चों पर प्रदूषण के प्रभाव को गंभीर माना गया है। लंबे समय तक प्रदूषण और धुएँ के संपर्क में रहने वाली महिलाओं में साँस से जुड़ी समस्याएँ और कई स्वास्थ्य जोखिम लगातार सामने आए हैं। यह किसी सिद्धांत की बात नहीं–भारत की करोड़ों महिलाओं की रोज़मर्रा की वास्तविकता है।

भारत में पर्यावरणीय नीतियाँ अक्सर सामान्य नागरिक के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन यह सामान्य नागरिक व्यवहार में कई बार पुरुष अनुभव से परिभाषित हो जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी योजना समितियाँ, वायु-गुणवत्ता प्रकोष्ठ और राज्य जलवायु मिशनों में महिलाओं की उपस्थिति सीमित है। परिणामस्वरूप नीतियों में महिलाओं के अनुभव और जोखिम कम ही जगह पाते हैं। शहरों की वायु-गुणवत्ता योजनाओं में सड़क किनारे काम करने वाली महिलाओं का उल्लेख लगभग नहीं के बराबर होता है। हीट-एक्शन प्लान गर्भवती मजदूरों के जोखिम को ध्यान में नहीं रखते। जल योजनाएँ यह मानकर चलती हैं कि पानी घर या मोहल्ले के नल तक ही सीमित एक संसाधन है, जबकि ग्रामीण भारत में पानी ढोने का बोझ आज भी मुख्यतः महिलाओं और लड़कियों के कंधों पर है।

दुनिया तेजी से यह स्वीकार कर रही है कि जलवायु

न्याय और जेंडर न्याय अलग-अलग प्रक्रियाएँ नहीं, बल्कि एक-दूसरे की पूरक शर्तें हैं। महिलाएँ केवल संकट की भोगी नहीं हैं, बल्कि समाधान की महत्त्वपूर्ण साझेदार भी हैं। कई अंतरराष्ट्रीय मंचों ने इसे स्पष्ट रूप से मान्यता दी है। भारत ने इस दृष्टि का समर्थन किया है, लेकिन घरेलू नीति और संस्थागत ढाँचे में यह परिवर्तन उतनी मजबूती से परिलक्षित नहीं होता।

पर्यावरणीय शासन में महिलाओं को केंद्र में रखना किसी बड़े विस्थापन या जटिल बदलाव की माँग नहीं करता। यह कुछ स्पष्ट और व्यवहारिक कदमों पर निर्भर है जैसे निर्णय-स्तर पर महिलाओं की उचित भागीदारी, स्वास्थ्य और श्रम नीतियों में जेंडर दृष्टि को शामिल करना, जेंडर-संवेदी बजटिंग के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षित पानी और ताप-सहिष्णु कार्यस्थलों को प्राथमिकता देना, और स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय संसाधन प्रबंधन में नेतृत्व देना। कई राज्यों में स॥त ने जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधन सुरक्षा में जो भूमिका निभाई है, वह बताती है कि अवसर मिलने पर महिलाएँ न केवल बदलाव लाती हैं, बल्कि उसे स्थायी भी बनाती हैं।

2-3 दिसंबर की भोपाल त्रासदी हमें यह याद दिलाती है कि औद्योगिक और पर्यावरणीय जोखिम कभी बराबरी से नहीं बँटते। आज जब विषैली हवा, पानी की कमी, असुरक्षित आवास, अनियमित मजदूरी और बढ़ती गर्मी हमारे शहरों और गाँवों की दिशा बदल रही है, तब यह साफ दिखाई देता है कि जलवायु संकट कोई दूर की चेतावनी नहीं यह लाखों महिलाओं की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। पानी भरने की कतारें, धुएँ से भरे रसोईघर, अस्थिर आय, और स्वास्थ्य पर बढ़ते जोखिम–यह हमारे समय का सबसे चुपचाप लिखा जा रहा लैंगिक अध्याय है।

अब वक्त है कि इस संरचनात्मक चुप्पी को तोड़ा जाए। निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की उपस्थिति न केवल बढ़नी चाहिए, बल्कि केंद्रीय भूमिका के रूप में स्वीकृत होनी चाहिए। राष्ट्रीय योजनाओं से लेकर स्थानीय निकायों तक, जहाँ भी हवा, पानी, जलवायु और शहरी ढाँचों से जुड़े फैसले होते हैं, वहाँ महिलाओं की भागीदारी को संख्या और भूमिका दोनों स्तरों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अतीत की त्रासदियों और वर्तमान के संकटों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पर्यावरणीय जोखिम हमेशा कमजोर समूहों को पहले और अधिक चोट पहुँचाते हैं। इसलिए जेंडर-संवेदी डेटा, नीति और बजटिंग को भारत की विकास रणनीति का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा।

भारत तभी आगे बढ़ेगा जब वह यह समझेगा कि स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और टिकाऊ विकास की लड़ाई केवल पर्यावरण की नहीं–यह महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और समान अवसरों की लड़ाई भी है।

विश्व दिव्यांगता जागरूकता दिवस

स्मिता कुमारी
लेखिका पुनर्वास मनोवैज्ञानिक एवं सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र, भोपाल की निदेशक हैं।

दिव्यांगता पर चुप्पी समाधान नहीं !

ऋषभ (परिवर्तित नाम) जन्म से ही अन्य बच्चों की तुलना में चीजों को देरी से सीखता था। मां को 3-4 साल की उम्र में समझ आ गया कि उनके बच्चे के विकास में कोई समस्या है। उन्होंने ऋषभ की थेरेपी शुरू कराई। इस थेरेपी से उनके बच्चे के व्यवहार के साथ-साथ सेल्फ केयर में काफी बेहतर विकास हुआ। ऋषभ अन्य बच्चों से ज्यादा संवेदनशील हो गया। वह अपना और अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखने लगा। मगर शिक्षा में बौद्धिक रूप से कमजोर होने के कारण वह बहुत पीछे था।

अब वह 12-13 साल का हो गया लेकिन मां के अलावा घर के हर सदस्य का व्यवहार उसके प्रति पढ़ाई ना कर पाने से कठोर रहता है। उन्हें लगता है कि यह बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो किसी योग्य नहीं बन पाएगा। वह सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि उनके बच्चे में कोई दिव्यांगता है। वह अकसर इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि वह बाहर उसके साथ शर्मिंदा महसूस करते हैं।

एक ऐसा ही उदाहरण अनुरुद्ध (परिवर्तित नाम) का है। जब 3 साल का था तब उसका परिवार उसके विलम्ब विकास की जांच के लिए लाएं, जांच में ऑटिज्म पता चला। वह इस बात को स्वीकार करके थेरेपी कराने की बजाय 4-5 साल भटकते रहें। क्योंकि उनको यह स्वीकार नहीं था कि उनके परिवार में ऐसा बच्चा जन्म लेगा।

एक और उदाहरण साहिबा (परिवर्तित नाम) का है। उसका परिवार इस कारण जांच के लिए आए क्योंकि 12 साल की होकर भी वह कई अक्षर उल्टा-सीधा लिखती थी। उनके अभिभावक को बताया गया कि उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है। उनको लगा बच्ची पढ़ने में ध्यान नहीं देना चाहती जबकि वह पढ़ने में औसत थी। वह थेरेपी कराते थे मगर उसकी तकलीफ को समझने से इंकार करके। उन्हें बस बच्ची को शादी की उम्र से पहले उल्टा-सीधा लिखवाट ठीक कराना था।

ऐसे कई उदाहरण हैं मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में जहां जागरूकता की और स्वीकार्यता की कमी से कई बच्चों का बेहतर पुनर्वास का सपना आज भी सपना ही बना है। जिनके अभिभावक इस बात को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं वह कमियों की जगह ऐसे बच्चों के क्षमताओं पर ज्यादा ध्यान देकर उनमें सकारात्मक विकास करा लेते हैं। आमतौर पर शारीरिक दिव्यांगता या समस्याओं को लोग जल्दी स्वीकार कर लेते हैं जैसे - सेरेब्रल पालसी, मूक-बधिर, दृष्टिबाधित या रक्त सम्बंधित दिव्यांगता या बौनापन या एसिड अटैक। क्योंकि यह छुपाया नहीं जा सकता। यह सबको आसानी से दिखता है। इसलिए इनके अभिभावक मानसिक दिव्यांगता वालों की तुलना में स्वीकार जल्दी करते हैं। मगर कई ऐसे अभिभावक है जो स्वीकार करके इनकी थेरेपी नहीं कराते क्योंकि उनको लगता है ऐसे बच्चे जीवन में क्या ही करेंगे।

ऐसे बच्चे क्या ही करेंगे? आइए इसे और टटोलते हैं:

1. हाल ही में ब्लाइंड महिला विश्व कप का परिणाम हमने देखा। यह वही महिला थी जिन्हें अवसर मिला तो विश्व को दिखा दिया कि ब्लाइंड भीख मांगने के लिए नहीं बल्कि अपने-अपने देश का नाम रौशन करने के लिए तैयार हैं। बस आप स्वीकार्यता, विश्वास और अवसर तो दीजिए।

2. कई पैरालंपिक गेम्स में दिव्यांगजन अपने देश का परचम लहराते हैं। बस आपको अपने बच्चे की क्षमता पर काम करना है।

3. कई रेस्टोरेंट, मॉल, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब में हर केटेगरी से दिव्यांगजनों में परचम लहराया है।

4. आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, थॉमस एडिसन, अभिषेक बच्चन आदि ने यह दिखया कि कला और विज्ञान का क्षेत्र भी इनकी क्षमताओं के अनुसार इन्हें एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है।

5. इनका शीघ्र पहचान (अर्ली इंटरवेंशन) होने से समय पर थेरेपी और स्किल डेवलपमेंट पर कार्य किया जा सकता है।

अभिभावकों द्वारा बच्चे की दिव्यांगता शीघ्र स्वीकार

करने का प्रभावः

1. थेरेपी देर से शुरू होती है तो बेहतर परिणाम नहीं आ पाता। जन्म से छः साल की उम्र तक बच्चों में विकास तेजी से होती है, इसलिए इस उम्र में लगातार थेरेपी कराने से जल्दी बेहतर सुधार देखने को मिलता है।

2. अभिभावक खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर लेते हैं तो अपने बच्चे की क्षमताओं पर जल्द काम शुरू कर लेते हैं।

3. जब खुद सजग होते हैं तो स्कूल या अन्य सार्वजनिक स्थल पर ऐसे बच्चे के अनुकूल वातावरण निर्मित करने और कराने में अहम भूमिका निभाते हैं।

4. उनको जल्दी मालूम होता है कि उनके बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या सही है और क्या नुकसानदायक। जिससे केयर करने में मदद मिलती है।

5. बच्चे को अवहेलना कम झेलना पड़ता है क्योंकि उनका परिवार उनके साथ होता है। ऐसे में बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ती है।

6. अभिभावक जल्द ही अपने आस-पास ऐसे लोगों का सुरक्षात्मक कवच तैयार कर पाते हैं जो जिंदगी के विपरीत परिस्थितियों में उनके और उनके बच्चे के साथ खड़े हो सकें, समानुभूति रख सकें और हर सम्भव सहयोग कर सकें।

7. लीगल गार्जियनशिप, इंश्योरेंस, पॉलिसी, पेंशन, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण या अन्य शासकीय योजनाएं समझकर अपने बच्चे के लिए उनका लाभ ले पाते हैं।

8. सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कमी हर इंसान में होती है। इन कमियों को पाटने के लिए कई रिसर्च के आधार पर और संघर्षों के बाद कानून बनाए जाते हैं। इसी में से एक है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। यह ऐसे बच्चों पर टैग लगाने के लिए नहीं बनाया गया है। बल्कि इनको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, सुलभ और सुरक्षित माहौल बनाने के लिए, इनकी अधिकारों की रक्षा करने के लिए और एक बेहतर पुनर्वास के लिए बना है। यह अधिनियम इक्वलिटी के साथ इक्विटी भी प्रदान करता है।

इसके लिए सबसे पहले दिव्यांगता की शीघ्र पहचान करना, थेरेपी से जोड़ना, समय रहते स्वीकार्यता को बढ़ाना और साथ हर सार्वजनिक जगहों पर अभिभावकों द्वारा और विशेषज्ञओं द्वारा उनका अनुभव और इस यात्रा को साझा करना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्?यूएचओ, 2023) के अनुसार, विश्व की 16 प्रतिशत आबादी यानी लगभग 1।3 अरब लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांगता का अनुभव करते हैं। भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस -5, 2019-21) के अनुसार, 4।52 प्रतिशत आबादी (लगभग 6।3 करोड़ लोग) दिव्यांग हैं, जिनमें लोकोमोटर दिव्यांगता सबसे अधिक 44।73त्न है।

अनुभव साझा करना क्यों है जरूरी?

इस पर खुल कर बात होने और अपने अनुभव साझा करने से आप अपने बच्चे के लिए सहज वातावरण तो बनाते ही हैं साथ ही वैसे अभिभावकों को प्रेरणा और हिम्मत मिलती है जो अभी-अभी इस दौर से गुजर रहे होते हैं।

तो खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए सहजता लाने के लिए अपने थैरेपीयूटिक जर्नी और विकास पर पोस्ट लिखिए, बात कीजिए, शेयर कीजिए। यह आसान तो नहीं है लकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे आसान होगा भी नहीं। और जब तक इस विषय पर खुलकर अपने अनुभव साझा नहीं करेंगे तब तक आपके और आपके बच्चे की क्षमताओं को और आपके पहचान को ब्लर तस्वीरों और परिवर्तित नामों के पीछे ही दबाया जाता रहेगा।

याद रखिए दिव्यांगता एक समस्या है जिस पर सभी तरह की प्रिकॉशन के बावजूद कई बार कंट्रोल नहीं होता, मगर चुपी रखना समाधान नहीं, छुपना-छुपाना समाधान नहीं। लेकिन यह भी सच है कि समाधान हमेशा हमारे हक में, हमारे हाथ में हैं। तो इस बार की विश्व दिव्यांगता जागरूकता दिवस की थीम 'सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांगजन समावेशी समाजों को बढ़ावा देना' को सार्थक बनाने के लिए खुलकर स्वीकार कीजिए। सामाजिक दूरी बनाने की बजाय लोगों से मेलजोल कीजिए, बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जोड़िए, खुद भी इस विषय पर सहज बनिए और समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक एवं संवेदनशील बनाइये।

ज्ञान की ऊर्जा से आलोकित- प्रकाशित हुई राजा भोज की धारा नगरी

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हजारों कंठों से गुंजायमान 15वां अध्याय

(राजेश शर्मा-धार)

1 दिसंबर को शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध धारा नगरी योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के गीता के संदेशों को हजारों - हजार कंठों से गुंजायमान कर मानों दिव्यता का संदेश दे रही थी। अवसर था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की पावन बेला का। राजा भोज की ऐतिहासिक धरा इस दिव्य- भव्य गरिमामय धार्मिक आयोजन की साक्षी बनी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की पावन बेला में धार नगरी और जिले में हजारों कंठों से एक साथ श्रीमद्भगवद्गीता के 15 वें अध्याय का सस्वर वाचन किया गया तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों संपूर्ण धरा पर ज्ञान और भक्ति का दिव्य वातावरण प्रवाहित हो रहा हो। इस ऐतिहासिक आयोजन में जिलेभर से हज़ारों - हजार हाथों ने भाग लेकर आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया।

मुख्यमंत्री की मंशा का सफल क्रियान्वयन हुआ धार की धरा पर- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार, यह महोत्सव मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, जिला प्रशासन धार, विश्व गीता प्रतिष्ठानम, परशुराम कल्याण बोर्ड और वीर भारत न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन की सफलता में विश्व गीता प्रतिष्ठानम के संयोजक संतोष पांडेय और विश्व गीता प्रतिष्ठान कार्यक्रम प्रभारी व परशुराम कल्याण बोर्ड के अशोक मनोहर जोशी और उनकी टीम का 15 दिनों का अथक परिश्रम निहित है । जिन्होंने विश्व गीता प्रतिष्ठानों से प्राप्त 4000 श्रीमद् भागवत गीता पुस्तकों का वितरण जिले की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला प्रशासन के माध्यम से वितरित करवाई।

महोत्सव की शुरुआत भगवान श्री सांवरिया सेठ मंदिर से हुई - महोत्सव की शुरुआत भगवान श्री सांवरिया सेठ मंदिर, त्रिमूर्ति नगर से हुई, जहाँ विश्व गीता प्रतिष्ठानम के संयोजक पंडित संतोष बाबूलाल पांडेय, गीता संगोष्ठी भक्त मंडल के पंडित अशोक मनोहर जोशी, सांवरिया सेठ मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी स्वयं प्रकाश सोनी की उपस्थिति में गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया। पीजी कॉलेज की संस्कृत की छात्राओं और गौतम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सामूहिक वाचन किया। मुख्य अतिथि न्यायाधीश प्रदीप सोनी और विशिष्ट अतिथि आईपीएस सुजावल जग्गा थे। अध्यक्षता धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री ने की। डीईओ केशव वर्मा, एपीसी प्रवीण शर्मा वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक जैन एवं युवा पार्षद अजीत जैन विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मोटिवेशनल स्पीकर, वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा ने किया।

पीजी कॉलेज में आयोजित मुख्य समारोह के मुख्य वक्ता के रूप में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पूर्व कुलगुरु डॉ. प्रभुनारायण मिश्रा थे। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार जी मेड़ा थे। अध्यक्षता अपर कलेक्टर संजीव केशव पांडेय ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री एवं सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित विश्वास पांडे थे।

मुख्य वक्ता डॉ. प्रभुनारायण मिश्र ने अपने उद्बोधन में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को बहुत ही मार्मिक तरीके से समझाते हुए गीता की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर विभिन्न उद्धरणों से प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि गीता जीवन प्रबंधन का महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। संतों, महात्माओं और महापुरुषों

द्वारा अपने उपदेश एकांत में दिए हैं लेकिन गीता का संदेश भगवान श्रीकृष्ण ने युद्ध के मैदान से संपूर्ण ब्रह्मांड को दिया। गीता सुख और दुख में समभाव की प्रेरणा भी देती हैं। गौरतलब है कि मुख्य वक्ता डॉ. मिश्रा के द्वारा गीता की प्रासंगिकता के संबंध में कई पुस्तकों का प्रकाशन करवाया गया है। स्वागत भाषण विश्व गीता प्रतिष्ठानम के संयोजक पंडित संतोष बाबूलाल पांडेय द्वारा देते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। मुख्य अतिथि परिचय परशुराम कल्याण बोर्ड के अशोक मनोहर जोशी द्वारा दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित गोपाल जोशी की वेद पाठी टीम के द्वारा उपस्थित सुधीजनों के समक्ष मंत्रोच्चार के द्वारा 15वे अध्याय का सस्वर पाठ करवाया गया। विश्व गीता प्रतिष्ठान द्वारा स्वागत करते हुए उन्हें श्रीमद् भागवत पुस्तिका तुलसी माला एवं प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए, वहीं नूपुर कला केंद्र की निदेशक वैशाली देशमुख के निर्देशन में सत्यभामा नृत्य नाटिका का अभूतपूर्व मंचन किया गया। अतिथियों को जिला प्रशासन की ओर से भी प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण शर्मा द्वारा किया गया तथा आभार रितेश शर्मा द्वारा किया गया।

छात्राएँ बनीं साक्षी....- भोज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में करीब 500 छात्राओं ने गीता स्वाधायी श्रीमती साधना वर्मा के निर्देशन में सामूहिक सस्वर पाठ किया।

युवा शक्ति का योगदान....- उत्कृष्ट विद्यालय में भी 350 छात्रों द्वारा गीता के 15वें अध्याय का वाचन किया गया।

ब्लॉकों में पाठ....- जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के नेतृत्व में जिले के सभी 13 ब्लॉकों की शिक्षण संस्थाओं में दोपहर 12 से 3 बजे तक सामूहिक वाचन हुआ।

खास-खास ....

- कृष्ण एवं सत्यभामा पर आधारित एक मनमोहक नृत्य नाटिका का मंचन भी किया गया।
- वीर भारत न्यास द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे खूब सराहा।
- इस अभूतपूर्व और गरिमामय आयोजन को सराहा गया।
- शहर में गीता महोत्सव की गूंज चहूंऔर सुनने को मिली। उत्कृष्ट विद्यालय, भोज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और धार जिला जेल में बैनर लगवाए गए थे जिसमें भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को संदेश देते हुए बताए गए हैं, जिन पर बच्चों के साथ-साथ आम जन का भी ध्यान केंद्रित रहा।

जेल में गीता संगोष्ठी- एक अभूतपूर्व क्षण...

कार्यक्रम की सबसे अनूठी और हृदयस्पर्शी कड़ी जिला जेल धार में देखने को मिली। जिला जेल के कैदियों ने गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक वाचन किया, जिसमें एक मुस्लिम भाई ने भी पूरे मनोयोग से स्वस्वर पाठ किया।

जेल अधीक्षक आर.आर. दांगी के निर्देशन में बंदियों ने 'सुदामा-कृष्ण मिलन' और 'भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश' की भाव-विभोर कर देने वाली नृत्य नाटिकाएँ प्रस्तुत कीं। जेल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सहायता के न्यायाधीश प्रदीप सोनी थे, अध्यक्षता अपर कलेक्टर संजीव केशव पांडे द्वारा की गई, विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्व गीता प्रतिष्ठा के संतोष पांडेय, सांवरिया सेठ मंदिर के अध्यक्ष स्वयं प्रकाश सोनी एवं परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित अशोक मनोहर जोशी उपस्थित रहे।
जिला जेल धार में दो दिवस पूर्व भी विश्व गीता प्रतिष्ठानम के संयोजक पंडित संतोष पांडेय एवं परशुराम कल्याण बोर्ड के प.अशोक मनोहर जोशी ने जेल अधीक्षक डांगी से मुलाकात कर जेल में बंदी लोगों को गीता की पुस्तके वितरित की गई। जिला जेल में पूरे जिले सहित 190 बंदियों द्वारा विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजित परीक्षा में भी हिस्सा लिया गया।

समापन सत्र में ज्ञान-गंगा....

गीता संगोष्ठी परिवार के ओमप्रकाश सोलंकी ने बताया कि महोत्सव का समापन सायं 6:30 बजे पीजी कॉलेज के सभागृह में हुआ। जहां विभिन्न स्कूलों से उपस्थित करीब 400 बच्चों को गीता की पुस्तक वितरण की गई।

विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं पीजी कॉलेज के 400 बच्चों ने वेद पाठियों के साथ 15वें अध्याय का वाचन किया। इस अवसर पर पीजी कॉलेज प्राचार्य बघेल, संस्कृत विभाग के डॉ. केशर सिंह चौहान सहित पूरा स्टाफ एवं एनएसएस के छात्र भी उपस्थित रहे।

एसआईआर की सीमा बढ़ी, लाभ उठाएं

बैतूल। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अन्तर्गत स्वीप गतिविधियों के माध्यम से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जेएच कॉलेज में प्राचार्य मीनाक्षी चौबे के संरक्षण में आज विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी प्रो.शंकर सातमकर ने विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता जागरूकता अभियान एसआईआर 2003 में मतदान केन्द्र व सरल क्रमांक डालने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। जिला संगठक डॉ. जीपी साहू द्वारा मतदान जागरुकता पर कार्यशाला में विशेष गहन पुनरीक्षण के महत्व एवं वोटर के कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। जेएच महाविद्यालय के हेल्प डेस्क प्रभारी की खेमचंद साहु हारा बीएलओ द्वारा पर्ची भरने की विस्तृत जानकारी छात्र-छात्राओं को दी गई। विशेष पुनरीक्षण पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रिया ओमकार द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। प्रश्नमंच प्रतियोगिता में 27 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की गई। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अध्यापक डॉ.पल्लवी दुबे, प्रो. गीता माली, प्रो.रूपेश सोनी, मंगल सिंह घुर्वे द्वारा उपस्थित रहकर एसआईआर को लेकर छात्र-छात्राओं को मार्गदर्शन दिया गया। इसमें इश्तियाक अली, सुमित घिड़ोड़े, आयुष नागोरे सहित 70 छात्र-छात्राओं सहभागिता की।

कलेक्टर ने संयुक्त तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को संयुक्त तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने तहसील कार्यालय बैतूल में जाति प्रमाण पत्र शाखा, नाजिर शाखा, न्यायालय बैतूल शहरी, न्यायालय बैतूल ग्रामीण, न्यायालय बैतूल बाजार का निरीक्षण कर प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने न्यायालय बैतूल बाजार में राजस्व प्रकरण लंबित पाए जाने पर और प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर रीडर के 5 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने राजस्व अभिलेख के डिजिटाइजेशन कार्य का भी अवलोकन कर जानकारी ली। नायब तहसीलदार श्याम सिंह उईके ने बताया कि जिले में 22 लाख अभिलेख के लक्ष्य के विरुद्ध 18 लाख अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा कर लिया गया हैं। उन्होंने शेष बचे डिजिटाइजेशन को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कार्यालय में साफ सफाई नहीं पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और कार्यालय नाजिर के एक दिन का वेतन काटने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि नवनिर्मित भवन का रखरखाव अच्छे से किया जाएं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कार्यालय आए लोगों से चर्चा भी की और उनके आवेदनों के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान तहसीलदार ग्रामीण गोवर्धन पाठे, तहसीलदार बैतूल श्याम सिंह उईके सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें।

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में स्वास्थ्य विभाग का उत्कृष्ट प्रदर्शन

बैतूल। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में बैतूल जिले ने प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि पर नेशनल हेल्थ मिशन की मिशन संचालक डॉ.सलोनी सिडाना ने बैतूल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मनोज हुरमाड़े को प्रशस्ति पत्र दिया है।सीएमएचओ डॉ.मनोज हुरमाड़े ने बताया कि प्रदेश में नागरिकों को संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना एवं जननी सुरक्षा योजना प्रमुख हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य गर्भवती महिलाओं को समय पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, एएनसी जांच, संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन तथा पौष्टिक आहार एवं मजदूरी क्षतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है, जिससे उनके पोषण स्तर में सुधार हो सके।

हेलो...दिल्ली बम ब्लास्ट और पुलवामा अटैक मामले के तार आपसे जुड़े हैं, बचना चाहते हो, तो पैसे लेकर आ जाओ

ईडी-सीबीआई अधिकारी बनकर रची थी साइबर ठगी की पूरी कहानी, 3 दिन तक रखा रिटायर्ड WCL कर्मचारी को 'डिजिटल अरेस्ट'

एस. द्विवेदी, बैतूल। जिले में एक बार फिर सायबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। पाथाखेड़ा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के एक मामले में तत्परता दिखाते हुए डब्ल्यूसीएल के रिटायर्ड कर्मी की जीवन भर की कमाई को ठगों के हाथो से बचा लिया है। पुलिस कन्ट्रोल रुम में मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेन्द्र जैन ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। उनके मुताबिक चैतराम नरवरे, उम्र 64 वर्ष, वर्तमान निवासी अशोका गार्डन भोपाल (रिटायर्ड डब्ल्यूसीएल कर्मचारी) को साइबर ठगों द्वारा तथाकथित डिजिटल अरेस्ट में फंसाकर डराया-धमकाया जा रहा था। वीडियो कॉल के माध्यम से ठगों द्वारा स्वयं को ईडी व सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को गलत लेन-देन के झूठे आरोप में फंसाने का डर देकर भयभीत कर रहे थे। वे मामले को टालने के नाम पर बड़ी धनराशि की मांग कर रहे थे। पीड़ित रिटायर्ड डब्ल्यूसीएल कर्मचारी चैतराम नरवरे स्वयम अपने बेटे व परिजनों के साथ पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए थे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि ठग कह रहे थे कि उनका एक अकाउंट केनरा बैंक मुंबई में है, तथा उस खाते से दिल्ली बम धमाके एवं पुलवामा अटैक के लिए लेनदेन होने की बात सामने आई है। उनका कनेक्शन इन आतंकी मामलों से होने की आशंका है। यदि बचना चाहते हो, तो पैसे लेकर होटल आ जाओ, पीड़ित द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा को खतरा होने के डर से ठगों के कहने पर भोपाल से पाथाखेड़ा आ गए थे। ठगों ने उन्हें गेस्ट हाउस में रुकवाकर परिवारजनों व परिचितों से संपर्क करने से भी रोक दिया था। पीड़ित अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, जो एसबीआई पाथाखेड़ा शाखा में 73 लाख की एफडी के रूप में थी, उसे तुड़वाकर आरटीजीएस द्वारा ठगो को देने हेतु बैंक से लेकर आए थे। जब परिजनों ने उनसे संपर्क किया, तो वे काफी घबराए हुए थे।

परिजनों ने किया पुलिस सम्पर्क - परिजनों को इस पर शक होने पर उन्होंने इसकी सूचना भोपाल पुलिस व साइबर सेल को दी गई। वही पीड़ित के बेटे पुष्कर नरवरे के द्वारा डिजीटल अरेस्ट की जानकारी अपनी मौसी के बेटे बैतूल बडोरा निवासी दीपेन्द्र मारवाड़ी दी। दीपेन्द्र को जानकारी लगते ही वह बैतूलबाजार थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने मोबाइल नंबर से उनकी लोकेशन ट्रेस की। यह लोकेशन पाथाखेड़ा के गेस्ट हाउस की मिली। इस सूचना पर चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा उप निरीक्षक मनोज कुमार उइके, प्रधान आरक्षक ज्ञानसिंह तेकाम, आरक्षक रविनाह आरक्षक राकेश करपे तथा सैनिक सुभाष की टीम राजेश गेस्ट हाउस पहुंची। टीम ने पीड़ित को सुरक्षित बाहर निकालकर विस्तृत रूप से बातचीत की। पीडित तीन दिनों से चल रहे इस घटनाक्रम पर मानसिक रूप से बेहद सदमे की स्थिति में था और पुलिस को वहां देखकर बहुत डर रहा था। पीड़ित को सुरक्षित चौकी लाकर पूरी घटना उसे विस्तार से समझाइ तथा उनके परिवारजनों से संपर्क स्थापित किया गया। इस दौरान थाना बैतूल बाजार प्रभारी सुश्री अंजना धुर्वे भी पीड़ित के मौसेरे भाई को साथ लेकर सीधे पाथाखेड़ा गेस्ट हाउस पहुँची और पुलिस चौकी पाथाखेड़ा को भी पूरी घटना समझाकर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि समय रहते, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो साइबर ठग पीड़ित से उसकी जीवन भर की मेहनत की पूरी कमाई एक बार मे ही हड़प लेते।

ठगी से बचने 1930 पर करें कॉल- उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन में साइबर ठगी से बचाव हेतु लगातार आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में लगातार विशेष अभियान चलाकर स्कूल, कॉलेज एवं सार्वजनिक स्थलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे है। साथ ही समस्त थाना प्रभारी को ऑनलाइन ठगी साइबर अपराधों में कमी ले जाने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई किए जाने निर्देशित किया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी, एसडीओपी सारणी सुश्री प्रियंका करचांग एव थाना प्रभारी सारणी जयपाल इवनाती के मार्गदर्शन में ठगी की इस बड़ी साजिश को नाकाम किया जा सका। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अनुरोध है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द या प्रक्रिया भारतीय कानून में कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। कोई भी एजेंसी-चाहे वह पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य कोई सरकारी विभाग हो, वे वीडियो कॉल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते और ना ही धनराशि की मांग कर सकते है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को अधिकारी बताकर ऑनलाइन माध्यम से आपको डराने या धमकाने का प्रयास करता है, तो समझ ले कि वे साइबर ठग है। कृपया ऐसे किसी भी कॉल पर विश्वास न करें, अपनी निजी बैंकिंग जानकारी साझा न करें और तुरंत 1930 (हेल्पलाइन) अथवा नजदीकी थाने को सूचना दें।

असम और दुबई से आ रहे थे कॉल- एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि साइबर ठगी के मामले में अधिकांश कॉल आजकल असम और दुबई से आ रहे हैं, लेकिन इन्हें ट्रेस करने में दिक्कतें आती है कि कौन-कहां से चैटिंग कर रहा है। देश भर में अब तक 1 लाख 23 हजार से ज्यादा लोग 'डिजिटल अरेस्ट' एवं लाखों साइबर ठगी का शिकार हो चुके है, इनमें ज्यादातर मामले बुजुर्ग लोगों, वरिष्ठजनों को डिजिटल अरेस्ट करने के मामले है। प्राय देखा गया है कि ये लोग सायबर मामले के ज्यादा जानकार नही होते है इसलिए इन्हे ठग आसानी से अपना शिकार बना लेते है। इसलिए ऐसे ठगो से सतर्क रहने की जरूरत है।

केवाईसी अपडेट के नाम पर खाते से उड़ाए हजारों, फिर चढ़ा 3.25 लाख का लोन

बैतूल। एक फोन कॉल आपकी जिंदगी की सारी कमाई को पलभर में निगल सकता है। साइबर ठग अब नए-नए तरीकों से लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम भडूस से सामने आया है। ग्राम भडूस निवासी संतोष कुमार गोहिते पिता भगवतीप्रसाद गोहिते ने एक्सिस बैंक बैतूल शाखा में बड़ी धोखाधड़ी की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि उनका खाता नंबर 914010003991403 है और एक अनजान नंबर से आए कॉल पर केवाईसी अपडेट के नाम पर उनकी पहचान संबंधी जानकारी लेकर उनके मोबाइल नंबर की जगह 9204925753 अपडेट कर दिया गया। संदेह होने पर वे बैंक पहुंचे और खाते पर होल्ड करवाया। लेकिन इसके बाद भी 17 अक्टूबर 2025 को उनके खाते से 69000 रुपये की निकासी कर ली गई। उन्होंने बैंक कर्मचारी राजकुमार से खाता बंद करने की मांग की, पर खाता बंद नहीं किया गया। उन्हें बताया गया कि उनका नंबर 9752825050 अपडेट कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा नहीं हो पाई। इसी दौरान उनके खाते में बिना अनुमति के 325276 रुपये का पर्सनल लोन स्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद 19 नवंबर 2025 को 7000 और 12000 रुपये, तथा 26 नवंबर 2025 को 17000 और 10000 रुपये के लेनदेन दिखे, जबकि उन दिनों श्रीजी शुगर मिल द्वारा लेबर और ट्रैक्टर किराये की राशि उनके खाते में जमा हुई थी। जब वे 27 नवंबर को बैंक पहुंचे और पैसे निकालने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि उनके खाते में कोई पैसा नहीं बचा है। संतोष कुमार गोहिते ने एक्सिस बैंक से इस पूरी धोखाधड़ी का समाधान और कार्रवाई की मांग की है।

नि:शक्त बालिका छात्रावास की छात्रा दुर्गा येवले ने रचा इतिहास

उत्कृष्ट प्रदर्शन कर महिला ब्लाइंड टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को बनाया विश्व विजेता

बैतूल। पहले टी-20 ब्लाइंड महिला वर्ल्ड कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाली ब्लाइंड क्रिकेटर दुर्गा येवले ने बैतूल ही नहीं पूरे मध्यप्रदेश और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। ऐतिहासिक सफलता हासिल करने वाली कुमारी दुर्गा बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील अंतर्गत रॉक्सी ग्राम के गौली ढाना की निवासी है। अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद दुर्गा ने निशक्त बालिका छात्रावास सदर बैतूल में पढ़ाई की थी। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा संचालित निशक्त बालिका छात्रावास में मिला मार्गदर्शन और प्रेरणा दुर्गा की ऐतिहासिक सफलता में मील का पत्थर साबित हुआ। वर्ल्ड कप विजेता महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की एतिहासिक सफलता पर दुर्गा येवले सहित अन्य महिला खिलाड़ियो को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देकर सम्मानित किया। कुमारी दुर्गा की उत्कृष्ट सफलता पर बैतूल जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, वरिष्ठ खिलाड़ियों, परिजनों, सामाजिक बंधुओं ने बधाई दी है। भैंसदेही तहसील के रॉक्सी ग्राम निवासी झब्बू येवले एवं श्रीमती गौरा येवले की बेटी ने दृष्टिबाधित होनें से अनेक चुनौतियों का सामना किया। लेकिन शिक्षकों से मिले मार्गदर्शन और प्रेरणा से उसने चुनौतियों का मुकाबला कर ऐतिहासिक सफलता हासिल की।

दुर्गा के मुताबिक निशक्त बालिका छात्रावास बैतूल में कक्षा 7 वीं एवं 8 वीं में पढ़ाई के दौरान वहां के माहौल से उसका आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ गई थी। जिससे ब्लाइंड स्कूल पाढर और महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ छात्रावास में पढ़ाई के दौरान बहुत मदद मिली। निशक्त बालिका छात्रावास सदर बैतूल की, तत्कालीन अधीक्षिका वर्तमान में अस्थि बाधितार्थ बालक उमावि बाल ग्रह बैतूल की प्रभारी अधीक्षक डॉ. सीमा भदोरिया के मुताबिक वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कुमारी दुर्गा येवले ने निशक्त बालिका छात्रावास बैतूल में रहकर कक्षा 7 वी एवं 8 वीं की पढ़ाई की थी। छात्रावास में निवासरत दिव्यांग बच्चियों को पढ़ाई के साथ जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, खेलकूद सहित अन्य विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। जिससे दिव्यांग बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ता था। डॉ सीमा भदौरिया के मुताबिक दुर्गा मेधावी छात्रा थी। कक्षा 8वीं के बाद उसे ब्लाइंड स्कूल पाढर, फिर इंदौर की संस्था में पढ़ने के लिए सतत मार्गदर्शन दिया गया। महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ छात्रावास इंदौर में पढ़ाई के दौरान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन एमपी के अध्यक्ष सोनू गोलकर ने दुर्गा की प्रतिभा को पहचाना और जिला स्तरीय ब्लाइंड टीम में मौका दिया।

संक्षिप्त समाचार

सीहोर में रोजगार मेला 09 दिसंबर को

सीहोर (निप्र)। युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 09 दिसंबर 2025 को प्रात: 11 बजे सीहोर स्थित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में रोजगार-स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेला आयोजित किया जाएगा। इस रोजगार मेले में रोजगार विभाग द्वारा स्थानीय, प्रदेश एवं अन्य राज्यों की कंपनियों को आमंत्रित कर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा स्वरोजगार विभागों के स्वरोजगार प्राप्त हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा तथा नये प्रकरण तैयार किये जायेगे। इसके साथ ही शासकीय आईटीआई द्वारा अप्रेंटिसशिप के लिये आवेदकों को चयनित किया जायेगा। इच्छुक आवेदक अपने मूल दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में उपस्थित हो सकते हैं।

जिला चिकित्सालय में नेत्र विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

नर्मदापुरम (निप्र)। जिला चिकित्सालय नर्मदापुरम के नेत्र विभाग की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस सत्र में नेत्र सहायकों और चिकित्सकों ने भाग लेकर विभागीय लक्ष्य पूर्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों पर चर्चा की। बैठक में प्रमुख रूप से नेत्र स्वास्थ्य के महत्व, कैटेरेक्ट की समस्या एवं समाधान, डायबिटीज रेटिनोपैथी के प्रभाव, नेत्रदान की प्रक्रिया, स्कूल हेल्थ स्पेक्टेकल्स के तहत बच्चों की आंखों की जांच व चश्मे वितरण, तथा ग्लॉकोमा की रोकथाम पर प्रकाश डाला गया। सभी ब्लॉक के ऑप्थेल टेक्नीशियन को लक्ष्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए इस अवसर पर डॉ. उदित कुमार भट्ट (नेत्र सर्जन), डॉ. रिचा गौर (डीपीएम, नेत्र विभाग), मनीषा, अनिता तथा अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। उन्होंने नेत्र सहायकों को लक्ष्य-पूर्ति हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया और नेत्रदान के महत्व को भी विस्तार से बताया।

लाडली बहना योजना से प्राप्त राशि से अपने बच्चे की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर रही श्रीमती नारायणी मनसोरिया

नर्मदापुरम (निप्र)। लाड़ली बहना योजना मध्यप्रदेश सरकार की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, परिवार की आय में सहयोग प्रदान करना तथा उन्हें स्वावलंबी बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका उपयोग वे अपनी आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरेलू जरूरतों के लिए कर सकती हैं। नर्मदापुरम निवासी श्रीमती नारायणी मनसोरिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लाड़ली बहना योजना के प्रभावी संचालन के लिए हृदय से धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है और इसके माध्यम से परिवारों को वास्तविक लाभ मिल रहा है। श्रीमती मनसोरिया ने बताया कि योजना के तहत प्राप्त होने वाली मासिक राशि का वे अपने बच्चे की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस तथा उनकी पढ़ाई से संबंधित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग करती हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना ने उन्हें आर्थिक रूप से काफी सहारा दिया है, जिससे वे अपने परिवार को बेहतर सुविधा प्रदान कर पा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्रीमती मनसोरिया ने कहा, 'हमारा आशीर्वाद है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव खूब तरक्की करें और प्रदेश में महिलाओं के हित में ऐसी ही योजनाएं आगे भी संचालित होती रहें।'

कलेक्टर ने अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए पूरी टीम और मतदाताओं को दी बधाई

सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बालागुरू के. ने जिले के सभी ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ सहित सीहोर जिले की पूरी टीम एवं मतदाताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सीहोर जिले की टीम ने अनुशासन, समर्पण और टीमवर्क का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह उपलब्धि जिले की मजबूत प्रशासनिक क्षमता और मतदाताओं के सहयोग का परिणाम है।' कलेक्टर ने मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जागरूकता और सक्रिय भागीदारी का इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री संजीव कुमार झा ने बताया कि प्रदेश में गणना पत्रकों के डिजिटलाइजेशन का कार्य तेज गति से जारी है। अभी तक मध्यप्रदेश के छ: जिलों अशोक नगर, नीमच, बैतूल, गुना, मंडला और सीहोर जिले ने एसआईआर का काम शत् प्रतिशत पूरा कर लिया है। श्री झा ने सभी शासकीय सेवकों और नागरिकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि सभी के समन्वित प्रयास और अथक परिश्रम से ही संभव हुई है। रविवार 30 नवंबर शाम तक 5 करोड़ 33 लाख से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है, जो कुल कार्य का लगभग 93 प्रतिशत है।

जिले में 925634 मतदाताओं को किया गया डिजिटाइज

भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया संशोधित एसआईआर-2026 कार्यक्रम कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना की मतदाताओं से अपील सभी मतदाता शीघ्र गणना प्रपत्र अपने संबंधित बीएलओ के पास अद्यतन कर जमा करे

नर्मदापुरम (निप्र)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नर्मदापुरम जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कार्य निरंतर प्रगति पर है। जिले में अब तक कुल 9,61,165 मतदाताओं में से 9,25,634 (96.30%) मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।विधानसभा सिवनी मालवा में कुल 2,48,509 मतदाताओं में से 2,42,500 (97.58%) का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, विधानसभा होशंगाबाद में 2,26,300 मतदाताओं में से 2,06,085 (91.07%) का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। जिसे प्राथमिकता से पूर्ण कराया जा रहा है। विधानसभा सोहागपुर में 2,47,213 मतदाताओं में से 2,46,277 (99.62%) का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है तथा विधानसभा पिपरिया में 2,39,143 मतदाताओं में से 2,30,772 (96.50%) का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है

कि गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित है। जिन मतदाताओं ने अभी तक अपने प्रपत्र जमा नहीं किए हैं, वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें एवं उसके पूर्व ही आवश्यक जानकारी सही, स्पष्ट और सत्य रूप से भरकर अपने बीएलओ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। केवल मृत, अपात्र एवं दोहरी प्रविष्टियों को हटाकर मतदाता सूची को अद्यतन किया जाएगा, जिससे एक सटीक, त्रुटिरहित एवं पारदर्शी मतदाता सूची सुनिश्चित की जा सके।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्ट्रक्र 2026 का संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया गया है, जिसके अनुसार गणना पत्रक भरने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025, दावा-आपत्ति अवधि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक, दस्तावेज़ सत्यापन 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा सभी कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्ट्रक्र 2026 की संपूर्ण प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक संचालित होगी, बीएलओ तीन बार घर-घर जाकर सत्यापन सुनिश्चित करें, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र भरकर जमा कर सकेंगे, फॉर्म-7 का उपयोग किसी प्रविष्टि को हटाने एवं फॉर्म-8 का उपयोग विवरणों में संशोधन के लिए किया जा सकेगा। एन्यूमरेशन फॉर्म में सही जानकारी देना मतदाता की जवाबदेही है, गलत जानकारी देने पर कार्रवाई संभव होगी।

योजना के तहत लाभान्वित श्री परते ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद

नर्मदापुरम (निप्र)। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय के युवाओं एवं हितग्राहियों को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने व्यवसाय, उद्योग या सेवा गतिविधि को सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकें। योजना का लक्ष्य ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, आर्थिक मजबूती प्रदान करना तथा परिवारों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है।

इसी क्रम में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत नर्मदापुरम जिले के श्री राजेंद्र परते को 2 लाख रुपये की ऋण राशि का चेक प्रदान किया गया। यह राशि उन्हें किराना व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु स्वीकृत की गई है। चेक प्राप्त होने के बाद श्री परते ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।

किराना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए मिली इस सहायता से श्री राजेंद्र परते न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं सेवा उपलब्धता को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा संचालित यह योजना राज्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता, उद्यमिता संवर्धन और आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

लगातार शतरंज की प्रतियोगिता से खिलाड़ियों का बढ़ा खेल का स्तर - कलेक्टर सिद्धार्थ जैन

हरदा (निप्र)। डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के द्वारा पांचवा चेस टूर्नामेन्ट का आयोजन रविवार को विद्या ग्रेस एकेडमी हरदा में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के मुख्य आतिथ्य में की गई। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने इतने उत्साह के साथ प्रतियोगियों में भाग लिया यह बहुत हर्ष की बात है। लगातार हरदा जैसी जगह में शतरंज प्रतिभागियों हो रही है, जिससे खिलाड़ियों का खेल का स्तर बढ़ गया है। निश्चित ही आने वाले समय में हरदा जिले का नाम प्रदेश ही नहीं देश के स्तर पर होगा।

चेस प्रतियोगिता में 94 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के 54 खिलाड़ी एवं ओपन वर्ग में 40 खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन अध्यक्ष श्री आलोक जैन, सचिव श्री पी.सी. पोर्ते, उपाध्यक्ष श्री जय शंकर कानवा, मिडिया प्रभारी श्री रोहित तिवारी, कोषाध्यक्ष श्री सत्यम बंसल, श्री विनोद उपाध्याय, श्री राजेश गौर, श्री राम गोपाल रघुवंशी, श्री गणेश पटेल, श्री अक्षय तोमर सहित बच्चों के माता-पिता एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशेष अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी श्री अशोक जैन ने विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया। प्रतियोगिता में अण्डर 14 वर्ग में प्रथम स्थान राघव द्विवेदी, द्वितीय स्थान लक्ष्य तनवानी, तृतीय स्थान वासु सिंह, चतुर्थ स्थान ऐकांश श्रीमाली एवं पांचवा स्थान आर्यन सोलंकी ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता में ओपन वर्ग में प्रथम स्थान हरदा कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने प्राप्त किया। वहीं द्वितीय स्थान अर्जव जैन, तृतीय स्थान दिलीप कुमार गुप्ता, चतुर्थ स्थान यश पचौरी, पांचवा स्थान अक्षय सिंह तोमर ने प्राप्त किया। साथ ही इस बार से हरदा स्टार ऑफ द सीटी के दो पुरूस्कार रखें गये, जो सद्दाम पठान एवं आलोकिक राय को दिये गये। कार्यक्रम के अंत में सचिव पी.सी. पोर्ते ने आभार व्यक्त किया।

आर्थिक संकट से जूझ रहीं ज्ञानबाई आजीविका मिशन की मदद से बनी आत्मनिर्भर

किराना दुकान से आर्थिक समृद्धि की अग्रसर हुई ज्ञान बाई

रायसेन (निप्र)। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर और राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका लाभ पाकर आज अनेक महिलाएं सफल उद्यमी हैं और परिवार की आर्थिक उन्नति में योगदान दे रही हैं।

रायसेन जिले के सिलवानी विकासखण्ड के ग्राम खमरिया मानपुर निवासी श्रीमती ज्ञान बाई भी उन लाखों महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने स्व-सहायता समूह से जुड़ने के अपनी मेहनत और लगन से परिवार की आर्थिक स्थिति को बदला है। सिलवानी तहसील मुख्यालय से 10 किमी दूर स्थित ग्राम खमरिया मानपुर में श्रीमती ज्ञान बाई अपने पति एवं एक बच्चे के साथ जीवन यापन करती थी। उनके पास दो एकड़ जमीन थी तथा परिवार पूरी तरह कृषि पर निर्भर था। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं होने से खेती में उत्पादन कम ही होता था। पानी के अभाव में मिट्टी की गुणवत्ता भी कम होने लगी और कृषि योग्य भूमि बंजर भूमि में बदलने लगी। प्रकृति की

मार व आर्थिक समस्याओं से जूझती श्रीमती ज्ञान बाई और उनके परिवार को पूर्णतः खेती पर आधारित होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कृषि भूमि से साल भर में लगभग 35 हजार रू की आय ही होती थी जिससे उनको परिवार को चलाने व मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पडता था।

ऐसे कठिन समय में श्रीमती ज्ञान बाई के जीवन में आजीविका मिशन आशा की किरण बनकर आया। श्रीमति ज्ञान बाई ने समूह व आजीविका मिशन की अवधारणा को समझने के बाद ग्राम में कृष्णा स्व-सहायता समूह का गठन किया और उसमें 10 सदस्यों को सम्मलित किया। समूह को चक्रिय राशि 20 हजार रूपये प्राप्त हुई। इससे समूह की बचत से रूपये लेकर आंतरिक लेन-देन करने लगीं। ज्ञान बाई के समूह ने समूह की दीदियों से चर्चा की और बैंक ऋण के लिए आवेदन तैयार किया, जिससे उनके समूह को बैंक लिंकेज के माध्यम से राशि प्राप्त हुई जिसका उपयोग सभी ने आजीविका गतिविधियों को बढ़ने के लिए किया।

डॉ0 वरूण कपूर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ मप्र भोपाल के द्वारा केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम का किया गया निरीक्षण

नर्मदापुरम (निप्र)। केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम खण्ड 'अ' में को डॉ0 वरूण कपूर, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ म0प्र0 भोपाल द्वारा निरीक्षण किया गया। महानिदेशक जेल के मुख्य आतिथ्य में नव निर्मित वी.सी. कक्ष का शुभारंभ किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल डिस्पेंसरी का निरीक्षण कर जेल चिकित्सक से बीमार बंदियों एवं बीमार बंदियों के उपचार संबंधी सुविधाओं की जानकारी ली गई। तत्पश्चात महिला वार्ड एवं पुरूष बैरिकों का निरीक्षण कर बंदियों से समस्या एवं जेल में प्राप्त होने वाली सुविधाएँ जैसे-भोजन, दवाईयाँ, मुलाकात, टेलीफोन सुविधा इत्यादि के विषय पर पूछताछ की गई। जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम से जेल में चल रहे गतिविधियों की जानकारी ली गई, जेल अधीक्षक श्री संतोष सोलंकी के द्वारा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ को अवगत कराया गया कि केन्द्रीय जेल

नर्मदापुरम के 94 प्रतिशत बंदी प्रतिदिन प्रातः समय योग एवं मेडिटेशन करते है, कलेक्टर जिला नर्मदापुरम के दिशा-निर्देश अनुक्रम में जेल के परिरूद्ध बंदियों को ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान नर्मदापुरम, नगरपालिका नर्मदापुरम, वनविभाग नर्मदापुरम, आईटीआई नर्मदापुरम, शासकीय पालीटेक्निक कॉलेज नर्मदापुरम, कृषि विभाग नर्मदापुरम एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों जैसे-सिलाई, इलेक्ट्रिशियन, एम.एस.आफिस, वर्मी कम्पोस्ट, फास्ट फूड, डेयरी फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। विभिन्न शासकीय विभागों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम के 2456 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया है जो कि परिरूद्ध बंदी संख्या का 95 प्रतिशत है।

महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ को जेल अधीक्षक नर्मदापुरम के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जेल से प्रशिक्षण प्राप्त रिहा बंदियों के शासन योजनांतर्गत वित्तीय सहायता हेतु ऋण प्रकरण तैयार कर विभिन्न संस्थाओं को भेजे जा रहे है अभी तक 100 से अधिक ऋण प्रकरण वित्तीय संस्थाओं को भेजे जा चुके है इसमे से 13 रिहा बंदियों को बैंक के माध्यम से स्वीकृत किये गये है। जिन बंदियों को ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये है वह अपने स्वरोजगार के माध्यम से जीविकोपार्जन कर रहे है। जेल के परिरूद्ध महिला बंदियों के द्वारा अंजनी शहरी स्वसहायता समूह का गठन किया गया है महिला स्वसहायता समूह के द्वारा नमकीन, अचार, गुड़ पट्टी, फल्ली दाने टेस्टी का निर्माण कर उत्पाद जेल केन्टीन सहकारी समिति को प्रदाय कर रहे है।

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक अभ्यास

बैतूल (निप्र)। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित समाज कार्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में यह कार्यक्रम विकासखण्ड समन्वयकों के मार्गदर्शन तथा परामर्शदाताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान विकासखंड समन्वयकों द्वारा 15वें अध्याय का पाठ, व्याख्या एवं अर्थ सरल भाषा में विद्यार्थियों को समझाया गया तथा उन्हें अपने-अपने कार्यक्षेत्र व ग्रामों में भी सामूहिक गीता पाठ कराने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं आभार व्यक्त किया गया तथा सभी ने प्रतिदिन गीता पाठ करने का संकल्प लिया।

बौद्ध विचार पर एकाग्र दो दिवसीय महाबोधी महोत्सव का समापन

रायसेन (निप्र)। संस्कृति विभाग, म.प्र. शासन द्वारा कलाओं में बौद्ध विचार पर एकाग्र दो दिवसीय महाबोधी महोत्सव का समापन शनिवार को बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क (पुराना विश्राम भवन परिसर), सांची में हुआ। जिला प्रशासन, रायसेन एवं महाबोधी सोसायटी ऑफ श्रीलंका के सहयोग से आयोजित समारोह में अंतिम दिन 30 नवंबर को श्रीलंका की ललिता गोमरा एवं साथी कलाकार लोकनृत्य एवं लोकगायन के माध्यम से श्रीलंका की संस्कृति को मंच पर लेकर आविर्भूत हुए।

समारोह की अंतिम सभा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की हुई, जहाँ सूर्यकुमार पाण्डेय (लखनऊ), स्वयं श्रीवास्तव (उन्नाव), सुमित मिश्रा (ओरछा), अभिसार शुक्ला (दिल्ली), हिमांशी बाबरा (मेरठ), मनु वैशाली (दिल्ली), दीपक शुक्ला (भोपाल) एवं चेतन चर्तित (इंदौर) ने कविता पाठ किया। श्रीलंका के दल ने प्रसिद्ध गीत हिमी सरनामर लोक शिवंकर... से भगवान बुद्ध को नमन किया कर मिथ मल पिपिदेवा... गाकर श्रोताओं के मन को आत्मिक शांति का एहसास कराया।

कार्यक्रम को विस्तार देते हुए मंगलम पूजा की प्रस्तुति दी,

यह प्रार्थना श्रीलंका में त्योहार के समय भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। पांच मिनट की इस अद्भूत प्रस्तुति के पश्चात भगवान बुद्ध को समर्पित पारंपरिक सिंहली गीतों की प्रस्तुति दी। कलाकारों ने प्रस्तुति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए वेस नृत्य लेकर मंच पर नमूदार हुए। किंवदंती के अनुसार इस नृत्य की उत्पत्ति कोहोम्बा कंकरिया (देवता) नामक एक नृत्य अनुष्ठान से हुई है, जिसे कोहोम्बा याक कंकरिया या कंकरिया भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मलया राता नामक स्थान के राजा और उसके भाइयों ने पहली कंकरिया नृत्य प्रस्तुति दी थी। इसकी उत्पत्ति भारत की भी मानी जाती है। कलाकारों ने यह नृत्य भगवान बुद्ध को समर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात कलाकारों ने बुद्धं शरणं गच्छामि... गीत पर नृत्य प्रस्तुति दी। सूर्यकुमार पाण्डेय ने पैकिंग पुरानी पड़ चुकी, लगेज वही है, क्या एज से होता है, ऑलवेज वही है... एवं दर्द के इन हज़ार घंटों में, हास्य का एक पल जरूरी है, बहुत टेंशन है यार लाइफ में... जैसी हास्य व्यंग्य की रचनाएं पेश की। स्वयं श्रीवास्तव ने दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूँ मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूँ मैं, आसान लग रहा है सफ़र देखने में पर, दीवानगी की आख़िरी हद तक गया हूँ मैं... एवं मुश्किल थी संभलना ही पड़ा, घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने 'शौक' रख दिया, हर 'शौक बदलना ही पड़ा, घर के वास्ते... रचना सुनाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। सुमित मिश्रा ने हर लमहे को ख़ास बनाया करते हैं, पीड़ा को एहसास बनाया करते हैं, कालजई कविता के हम आराधक हैं, घटना को इतिहास बनाया करते हैं... और नहीं किसी को कभी हताहत किया है हमने जग जानता है, सदा ही श्रद्धा का शुद्ध स्वागत किया है हमने जग जानता है... रचना पेश की। अभिसार शुक्ला ने उदासी चखती रहती है दुःखों को धार देती है, मोहब्बत कुछ नहीं करती है लड़के मार देती है..., जो धर्म की ध्वजा को देख-देख चल रहे हैं अस्त्र-अस्त्र से उठा है शोर-शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है..., वो राम जो है चेतना के बिंदु, बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज-तेज जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है अनाम है... रचना सुनाकर श्रोताओं को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इसके पश्चात मनु वैशाली ने बक्सों में उन घरों के, रक्खा है इक जमाना, तुम कह रहे हो वैसे गाँवों में क्या रखा... और जगती का मंगल अभिनंदन करने को, तन जोगन मन जीवन चंदन करने को, पांवों की पायल के घुंघरू सूचक है, इन पांवों के खुल के नर्तन करने को... तो चेतन चर्तित ने सब्र के बाँध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा, जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर ला दिया, वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा... एवं हर महफ़िल में हँसते गाते रहना हैं, हमको अपने दर्द छुपाते रहना है... रचना सुनाई। दीपक शुक्ला ने सुबह-सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते चार दनादन, ओलंपिक का दौड़ विजेता भी न लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ़्तार दनादन... एवं पापा सुनो मम्मी मुझे रोज-रोज मारती है, अपनी कहानी आज किसको सुनाऊं मैं, कभी तो पड़ोसियों के सामने ही कूटती हैं, लाज कैसे आज हाय अपनी बचाऊं मैं... रचना सुनाई।

2 दिसंबर भोपाल गैस कांड

मौत सामने थी, साथी दम तोड़ रहे थे...

डिप्टी स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर ने जो किया, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

भोपाल (नप्र)। रात डेढ़ बजे थे। भोपाल रेलवे स्टेशन पर जहरीली गैस का बादल छा चुका था। स्टेशन सुपरिंटेंडेंट और 23 साथी मिनटों में दम तोड़ चुके थे। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर एक शख्स अभी भी खड़ा था। नाम था, डिप्टी स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर। उनका गला रुका हुआ था, आंखें जल रही थीं, सांसें जवाब दे रही थीं। फिर भी उन्होंने वो किया जो शायद ही कोई कर पाता।

2 दिसंबर की रात क्या हुआ था?- भोपाल रेलवे स्टेशन पर 2 दिसंबर 1984 की मध्यरात्रि के बाद, स्टेशन के उप-स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। तभी उन्होंने एक जहरीली गैस का रिसाव महसूस किया। स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। कई लोग पहले ही दम तोड़ चुके थे, जिनमें उनके सीनियर भी शामिल थे। तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने गोरखपुर-मुंबई एक्सप्रेस को, जिसमें 1,000 से अधिक यात्री सवार थे, निर्धारित समय से 15 मिनट पहले रवाना करवाया और आसपास के स्टेशनों को भोपाल की ओर आने वाली ट्रेनों को रोकने के लिए सूचित किया।

वरिष्ठ अधिकारी की भी हुई मौत- उन्होंने बताया था कि उन्हें लगा कुछ सीरियस है तो वे तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी हरीश धुर्वे के कार्यालय की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उससे उनकी आशंका और बढ़ गई। उन्होंने देखा कि स्टेशन अधीक्षक पहले से ही जहरीली गैस के कारण दम तोड़ चुके थे। बाद में पता चला कि धुर्वे एक पोर्टर के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उत्तरी छोर की ओर भागे थे। वे एक एक्सप्रेस ट्रेन को भोपाल में बिना रुके गुजारने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रयास में, उन्होंने जहरीली गैस को सांस के साथ अंदर ले लिया और उनकी मृत्यु हो गई।

स्टेशन छोड़कर भाग गए कर्मचारी- उस समय स्टेशन पर बहुत कम कर्मचारी मौजूद थे। स्टेशन के 23 अन्य सहकर्मी भी इस घटना का शिकार हो चुके थे। तभी दस्तगीर को एहसास हुआ कि जहरीली गैस पूरे रेलवे स्टेशन को अपनी चपेट में ले चुकी है। उन्होंने गोरखपुर-मुंबई एक्सप्रेस को स्टेशन पर आते देखा। इस ट्रेन में 1,000 से अधिक यात्री सवार थे। दस्तगीर ने अपने वरिष्ठों को स्थिति के बारे में सूचित किया। लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी थी। किसी भी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना, उन्होंने उपलब्ध कर्मचारियों से ट्रैक खाली करने और ट्रेन को तुरंत रवाना करने का आदेश दिया। ट्रेन को उसके निर्धारित समय से 15 मिनट पहले रवाना कर दिया गया।

2003 में हुआ गुलाम दस्तगीर का निधन

इस बीच दस्तगीर खुद भी घुटन और सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। इसके बावजूद भी उन्होंने तुरंत आसपास के स्टेशनों को सूचित किया कि वे भोपाल की ओर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दें। उनके इस प्रयास से कई लोगों की जान बची। बाद में खुद दस्तगीर भी बेहोश हो गए और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बमुश्किल उनकी जान बची। इस घटना में स्टेशन के 23 कर्मचारी भी मारे गए थे। हालांकि गुलाम दस्तगीर का निधन 2003 में हुआ।

कौन सी गैस हुई थी लीक?

यह घटना भोपाल गैस त्रासदी का एक हिस्सा थी, जो दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। रिसाव के कारण हजारों लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। इस गैस के संपर्क में आने से लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं, जिनमें श्वसन संबंधी रोग, आंखों की समस्याएं और कैंसर शामिल हैं।

गैस त्रासदी की बरसी पर भाकपा का प्रदर्शन आज

यूनियन कार्बाइड से हुई भीषण गैस त्रासदी की 41 वीं बरसी पर गैस पीड़ितों को अधिकतम मुआवजा,इलाज, सम्मानजनक पेंशन सम्बन्धी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज 3 दिसम्बर को

पूर्वान्ह 11 बजे से स्थानीय मंगलवारा चौराहे पर थाने के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के अवसर पर गैस पीड़ितों की विभिन्न मांगों को लेकर भारत के राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन जिला भोपाल के कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को सौंपा जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भोपाल के सभी गैस पीड़ितों से अपील की है कि अपनी एकजुटता को अभिव्यक्त करें और इस प्रदर्शन में शामिल हों ।

48 घंटे तक भूखे रहकर ट्रेन चला रहे लोको पायलट, भूख हड़ताल पर गए

कहा- लंबे ड्यूटी आवर्स और लगातार मानसिक दबाव में गाड़ियां चलाते हैं

भोपाल (नप्र)। भारतीय रेलवे के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 48 घंटे की हंगर फास्ट (भूख हड़ताल) पर चले गए हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आव्हान पर 2 दिसंबर सुबह 10 बजे से 4 दिसंबर सुबह 10 बजे तक देशभर में 1 लाख 20 हजार लोको रनिंग स्टाफ बिना भोजन ड्यूटी करेगा।

मध्य प्रदेश में यह आंदोलन कटनी, जबलपुर, सतना, सागर, बीना, भोपाल, इटारसी, गुना, कोटा और गंगापुरसिटी की क्रू लॉबी में शुरू हो गया है। जोनल सचिव वीके जैन ने कहा कि लोको पायलट रेल सुरक्षा की रीढ़ हैं, लेकिन हमारी मांगों पर वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहा है। जैन ने कहा-हमें काम के प्रतिकूल हालात, लंबे ड्यूटी आवर्स और लगातार मानसिक दबाव में गाड़ियां चलानी पड़ती हैं। ऐसे में हम मजबूर होकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

एआईएलआरएसए की ये हैं 10 मुख्य मांगें

- ट्रैवलिंग अलाउंस (टीए) में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी के अनुपात में माइलेज भत्ते में वृद्धि।
- किलोमीटर भत्ते का 70 प्रतिशत आयकर मुक्त किया जाए।
- आवधिक विश्राम (पीआर) 46 घंटे (16+30) सुनिश्चित किया जाए।
- एएलपी से एलपीएम तक सभी पदों का वेतनमान रु 6 से एल-10 स्तर पर तय किया जाए।
- मेल-एक्सप्रेस में अधिकतम 6 घंटे और मालगाड़ी में 8 घंटे ड्यूटी का नियम लागू हो।
- लगातार दो रात से ज्यादा नाइट ड्यूटी न कराई जाए।
- 36 घंटे के भीतर मुख्यालय वापसी सुनिश्चित की जाए।
- एनपीएस बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
- लोको पायलट कौन-सी मजबूरियां गिना रहे?
- 9 घंटे ड्यूटी का नियम होने के बावजूद 12 से 16 घंटे तक लगातार संचालन
- कई बार 72 से 104 घंटे तक मुख्यालय से बाहर
- इंजनों में शौचालय-यूरिनल की सुविधा नहीं
- भोजन, लंच ब्रेक और उचित विश्राम का अभाव
- रिक्त पदों की भरमार–20 हजार से अधिक रनिंग स्टाफ की कमी
- सुरक्षा नियम लागू न होने से बढ़ता मानसिक दबाव
- बीमार पड़े तो ट्रेन संचालन पर असर हो सकता है

संघ ने स्पष्ट किया है कि यह विरोध शांतिपूर्ण होगा। जानबूझकर ट्रेन संचालन नहीं रोका जाएगा, लेकिन उपवास के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर अगर कोई लोको पायलट काम नहीं कर पाए, तो इसका असर ट्रेन संचालन पर पड़ सकता है।

प्रदेश में 5-6 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड

पहाड़ों में बर्फबारी से सर्द हवाएं भी आएंगी

तापमान 3 डिग्री तक गिरने के आसार

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में 5 या 6 दिसंबर से कड़ाके की ठंड शुरू होगी। वहीं कोल्ड वेव यानी, शीतलहर भी चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक, 5 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। पहाड़ों में बर्फबारी होगी और फिर बर्फीली हवाओं का असर एमपी में दिखेगा। मंगलवार से रात के पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है।

नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ने वाली तेज सर्दी का असर दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक बना रहेगा। इससे पहले रविवार-सोमवार की रात में भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 6 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। बड़े 5 शहरों में इंदौर में सबसे कम 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल में 9.4 डिग्री, ग्वालियर-उज्जैन में 12 डिग्री और जबलपुर में पारा 11.8 डिग्री रहा। प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। राजगढ़ में 8.2 डिग्री, रीवा-नौगांव में तापमान 9.5 डिग्री रहा। शिवपुरी, बैतूल, खजुराहो, खंडवा, दतिया,

छिंदवाड़ा में पारा 12 डिग्री से नीचे रहा।

दिन में ठंडक घुली...पारा 23 डिग्री तक आया- दूसरी ओर, सोमवार दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बालाघाट का मलाजखंड सबसे ठंडा रहा। यहां अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पचमढ़ी-शिवपुरी में 24.2 डिग्री, सिवनी में 24.6 डिग्री, बैतूल में 24.8 डिग्री, नरसिंहपुर में 25 डिग्री, टीकमगढ़ में 25.2 डिग्री भोपाल-धार में 25.6 डिग्री, रीवा में 25.8 डिग्री रहा।

नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ चुकी है सर्दी- इस बार नवंबर में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। भोपाल में लगातार 15 दिन तक शीतलहर चली। रिकॉर्ड के अनुसार, साल 1931 के बाद शीतलहर के यह सबसे ज्यादा दिन है। दूसरी ओर, 17 नवंबर की रात में पारा 5.2 डिग्री तक पहुंच गया, जो ओवरऑल रिकॉर्ड भी रहा। इससे पहले 30 नवंबर 1941 में तापमान 6.1 डिग्री रहा था। इंदौर में भी पारा 6.4 डिग्री ही रहा। यहां भी सीजन की सबसे सर्द रात रही।

वीआईटी यूनिवर्सिटी में हिंसा पर कांग्रेस का हंगामा

विधानसभा में बेहोश हुए कृषि मंत्री, नगर पालिका-परिषद अध्यक्षों के चुनाव अब डायरेक्ट होंगे

भोपाल (विसं)। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को अतिवृष्टि और वीआईटी विश्वविद्यालय को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इससे पहले कांग्रेस विधायक खेतों में फसलों की स्थिति को दर्शाती तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- प्रदेश का किसान कभी खाद के लिए, कभी उचित मूल्य के लिए तो कभी मुआवजे के लिए भटक रहा है।

कार्यवाही के बीच कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना को चक्कर आ गया। वे बेहोश हो गए। सीएम तुरंत कंसाना के पास गए। इसके बाद स्पीकर और बाकी लोग पहुंचे। कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।सदन में मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश- 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह संशोधन राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि पहले राइट टू रिकॉल ढाई साल में लागू होता था, जिसे अब 3 साल कर दिया गया है ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने

कहा कि इस बिल से जनता को कोई सीधा फायदा नहीं होगा। यह केवल टिकट बेचने का माध्यम बनेगा और 3 साल बाद फिर खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग होगी। शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी गई।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार- हॉर्स ट्रेडिंग तो सब जगह है, चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों या कोई और। नगर पालिका बिल से राजनीतिक फायदे ज्यादा हैं। जनता को इससे कोई सीधा फायदा नहीं है। यह बिल टिकट बेचने का माध्यम बनेगा। 3 साल बाद अध्यक्ष को राइट टू रिकॉल के दायरे में लाना ठीक नहीं है। उसका कार्यकाल पूरा होना चाहिए।

भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह- नगर पालिका परिषद के चुनाव जनता से कराने के विधेयक को सिरमौर से बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह ने सराहनीय कदम बताया है।

कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर- प्रदेश में 10-12 नगरीय निकायों के अध्यक्षों के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश था। कई अध्यक्षों को पार्षद और जनता हटाने की तैयारी कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह व्यवस्था उनको बचाने के लिए की गई हो। हालांकि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, क्योंकि इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुकेगी।

कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया- जहां विधायक बिकते हों, पार्षद बिकते हों, वहां इस राइट टू रिकॉल का कोई मतलब नहीं है। इस बिल में राइट टू रिकॉल होने के कारण 3 साल बाद फिर खुलेआम खरीद फरोख्त होगी।

नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी- देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसी के चलते अब नगरपालिका-नगर परिषदों के चुनाव जनता के माध्यम से होंगे।

दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इस पर 4 दिसंबर को 3:30 घंटे चर्चा होगी। दूसरा अनुपूरक बजट 13476 करोड़ 94 लाख रुपए का है।

बच्चों में स्मार्टफोन-इंटरनेट की लत रोकने की मांग

दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भाजपा विधायक डॉ. अभिलाष पांडे ने पेश किया। उन्होंने 14 साल से कम उम्र के बच्चों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती लत को रोकने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस समस्या की रोकथाम के लिए विद्यालयों और आंगनबाड़ियों के स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इसके लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।

मंत्री निर्मला- सरकार कर रही निगरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में निगरानी के प्रयास कर रही है। संबंधित एजेंसियां ऐसे मामलों में कार्रवाई कर रही हैं और बच्चों को पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी जा रही है। साथ ही बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि गाजियाबाद के सीएमएचओ द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है, जिस पर मध्यप्रदेश में भी अमल किए जाने की जरूरत है।

स्कूल की रेलिंग पर लटका मिला युवक का शव

रतलाम में सीएम राइज स्कूल की बाउंड्री पर गमछे से लगाया फंदा; मोबाइल स्विच ऑफ मिला

रतलाम (नप्र)। रतलाम के रावटी में मंगलवार सुबह एक युवक का शव बंद पड़े सीएम राइज स्कूल की बाउंड्रीवॉल की रेलिंग से लटका मिला। मृतक की पहचान 28 वर्षीय भानूप्रताप सिंह राठौर के रूप में हुई है। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रावटी के मंडी रोड पर स्थित बंद पड़े सीएम राइज स्कूल की रेलिंग पर सुबह 6.30 बजे राहगीरों ने शव लटका देखा। उन्होंने तुरंत उसे गांव के युवक के रूप में पहचाना और परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और फिर पुलिस को बुलाया। सूचना मिलने पर रावटी थाने के सब इंस्पेक्टर एमआई खान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। युवक ने गमछे से फंदा लगाया था और उसका मुंह स्कूल की दीवार से सटा हुआ था। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को फंदे से उतारा।

लापरवाही पर एक्शन...भोपाल में 75 इंजीनियर बीएलओ के सहायक बने

एसआईआर डिजिटाइजेशन का काम सौंपा, कमिश्नर को नहीं बता पाए थे अपना काम

भोपाल (नप्र)। भोपाल नगर निगम के कुल 75 असिस्टेंट और सब इंजीनियर सजा के तौर पर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के सहायक बना दिए गए हैं। ये निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को अपने सिविल से जुड़े काम की जानकारी नहीं दे सके थे। नाराज होकर कमिश्नर ने इन्हें बीएलओ का सहायक बनाते हुए एसआईआर डिजिटाइजेशन का काम सौंप दिया।

इंजीनियरों को यह अनोखी सजा 4 दिसंबर तक के लिए दी है। हालांकि आदेश 27 नवंबर को जारी हुआ था, तब एसआईआर की तारीख नहीं बढ़ी थी। दूसरी ओर कमिश्नर जैन साउथ कोरिया गई हुई हैं, जो 6 दिसंबर की सुबह लौटेंगी। ऐसे में प्रभारी कमिश्नर अंजू कुमार नया आदेश जारी करेगी।

इसलिए नाराज हुई कमिश्नर जैन - सभी इंजीनियर सिविल के हैं। बताया जाता है कि निगम कमिश्नर जैन ने असिस्टेंट और सब इंजीनियर से उनके सिविल के काम के बारे में पूछा था। जिसके बारे में 15 दिन में भी जवाब नहीं मिल सका था। जानकारी देने पर

देरी होने से कमिश्नर नाराज हो गई थीं। इसके बाद इनकी ड्यूटी विधानसभा के हिसाब से बीएलओ के सहायक के रूप में लगा दी।

आदेश में लिखा- सुबह 7 बजे से रात्रि चौपाल तक ड्यूटी करें- कमिश्नर जैन ने अपने आदेश में कहा है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी, ईआरओ जरूरत के हिसाब से इन इंजीनियरों का अन्य मतदान केंद्रों में भी उपयोग कर सकते हैं। यह प्रतिदिन सुबह 7 बजे से ड्यूटी करेंगे, जो रात्रि चौपाल खत्म होने तक मतदाताओं से गणना फार्म एकत्रित कर डिजिटाइजेशन का कार्य समय अवधि में करेंगे।

भोपाल में एसआईआर के तहत काम चल रहा है। अब तक 70 प्रतिशत से अधिक डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है।

आदेश में कहा- सिविल कार्यों में प्रगति नहीं

निगम कमिश्नर के आदेश में लिखा है कि नगर निगम भोपाल के सिविल कार्यों में प्रगति नहीं होने के कारण बूथ लेवल ऑफिसर के सहायक के रूप में इंजीनियरों की ड्यूटी लगाई जाती है।

विधानसभा के जिन बूथ पर काम कमजोर, वहीं लगाया

खास बात ये है कि सभी इंजीनियर को ऐसे बूथ पर तैनात किया गया है, जो परफार्मेंस परफॉरमेंस में फिसड्डी के मामले में टॉप-20 है। यानी, जो इंजीनियर अपने सिविल के काम सही ढंग से नहीं कर सके, उन्हें बूथ पर एसआईआर का जिम्मा सौंपा गया है।

सहायक यंत्री और उप यंत्रियों की विधानसभा वार तैनाती

इस मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि सहायक यंत्री और उप यंत्रियों की विधानसभा वार तैनाती की गई है। वे एसआईआर के काम में जुटे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाने को देश के श्रेष्ठ थानों की रैंकिंग में 9वां स्थान प्राप्त होने पर दी बधाई

मप्र में नहीं बनेंगे फर्जी डिसेबल सर्टिफिकेट, जांच होगी सटीक

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में अब फर्जी डिसेबल सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया अब और अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और एकीकृत होने जा रही है। एम्स भोपाल और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मिलकर पहली बार रिवाइज्ड डिसएबिलिटी असेसमेंट गाइडलाइंस पर राज्यस्तरीय वर्कशॉप आयोजित की। इसमें प्रदेश के सभी सात संभागों से मेडिकल बोर्ड के प्रतिनिधि, सिविल सर्जन और विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हुए। वर्कशॉप में विशेषज्ञों ने केस आधारित प्रशिक्षण देकर बताया कि गलत मूल्यांकन किस तरह मरीजों के अधिकारों को प्रभावित करता है और वैज्ञानिक मूल्यांकन कैसे राहत दे सकता है। पूरे राज्य में जल्द डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग और पंचायत स्तर पर स्क्रीनिंग कैंप शुरू करने की दिशा तय की गई।

एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) माधवानंद कर के नेतृत्व में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया। जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की वरिष्ठ संयुक्त निदेशक डॉ. प्रज्ञा तिवारी, हाईकोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के वरिष्ठ सलाहकार गुरमुख सिंह लांबा, आनंद सेवा सोसाइटी के संस्थापक ज्ञानेंद्र पुरोहित, एम्स के डीन डॉ. रजनीश जोशी समेत अन्य मौजूद रहे।

45 अधिकारी और डॉक्टरों ने लिया प्रशिक्षण

वर्कशॉप में मध्यप्रदेश के सभी सात संभागीय मेडिकल बोर्डों के चेयरपर्सन, आरडी ऑफिस से

मास्टर ट्रेनर और 10 जिलों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, धार और सीहोर) से आए सिविल सर्जन शामिल हुए। इसके साथ ही ऑर्थोपेडिक्स, नेत्र रोग और ईएनटी विशेषज्ञ भी तकनीकी सत्रों में शामिल रहे। यह पहली बार था जब राज्यभर के मेडिकल बोर्ड एक ही मंच पर आकर प्रमाणन की हर चरण प्रक्रिया पर प्रशिक्षण ले रहे थे।

इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा

लोकमोटर डिसएबिलिटी, मानसिक रोग, बौद्धिक अक्षम्यता व क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, विशेष शिक्षण अक्षमता/ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, श्रवण बाधितता, दृष्टि बाधितता, रक्त विकार, बहु विकलांगता